■ आषाढ़ शुक्ल - 5 ■ संवत 2081 ■ वर्ष - 11 ■ अंक - 342 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- चेन्नई » गुरुवार » 11-07-2024 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 पहले सरकारी भर्ती प्रक्रिया में चाचा-भतीजे की जोड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी: आदित्यनाथ

6 भारत-रूस मित्रता को जीवंतता देने का सार्थक प्रयास

7 रसोई गैस के फर्जी ग्राहकों की पहचान के लिए ई-केवाईसी सत्यापन : पुरी

फर्स्ट टेक

इजराइली सेना ने 'गाजा सिटी' को खाली करने का आदेश दिया

यरूशलम/एपी। इजराइली सेना ने 'गाजा सिटी' को खाली किए जाने का आदेश दिया है। इजराइली सेना ने यह जानकारी दी। 'गाजा सिटी' उन क्षेत्रों में शामिल है जिन्हें युद्ध की शुरुआत में निशाना बनाया गया था और अब वहां फिर से हमले किए जा रहे हैं। सेना ने शहर में पर्चे गिराए, जिनमें लोगों से दक्षिण की ओर जाने का आह्वान किया गया और कहा गया, ''गाजा सिटी एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र बना रहेगा।'' इजराइली सेना के इस आदेश से संभवत: यह संकेत मिलता है कि इजराइल शहर में भीतर तक घुस रहा है, जबकि हालिया दिनों में वह इसके कई बाहरी इलाकों में सक्रिय रहा है। यह इस बात का भी संकेत है कि हमास उन क्षेत्रों में फिर से संगठित हो रहा है, जहां से इजराइल ने उसका सफाया होने की बात कही थी।

टी20 विश्व कप जीत के बाद द्रविड़ ने बोनस राशि लेने से इनकार किया

नई दिल्ली/भाषा। भारत के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने हाल में टी20 विश्व कप में टीम की खिताबी जीत के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा ढाई करोड़ रुपये की अतिरिक्त बोनस राशि की पेशकश ठुकरा दी है। द्रविड़ को राष्ट्रीय टीम की सफलता के बाद बोनस राशि की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने अन्य कोचिंग स्टाफ के समान ढाई करोड़ रुपये लेने की इच्छा जताई। बारबाडोस में भारत की खिताबी जीत के बाद बीसीसीआई उन्हें खिलाड़ियों के समान पांच करोड़ रुपये देना चाहता था लेकिन पीटीआई को पता चला है कि यह 51 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर अन्य कोचिंग स्टाफ के समान राशि लेकर खुश है।

ईडी ने यूट्यूबर एल्विश यादव को धनशोधन मामले में समन भेजा

लखनऊ/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूट्यूबर सिद्धार्थ यादव उर्फ एल्विश यादव को उसके द्वारा आयोजित पार्टियों में नशे के लिए सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए 23 जुलाई को तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय एजेंसी ने मई में मामला दर्ज किया था और उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) जिले में पुलिस द्वारा एल्विश यादव और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी और आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप लगाए थे।

11-07-2024 सूर्यास्त 6:39 बजे	12-07-2024 सूर्योदय 5:49 बजे
BSE 79,924.77 (-426.87)	NSE 24,324.45 (-108.75)
सोना 7,606 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	चांदी 99,300 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

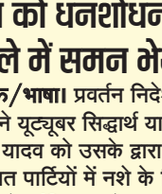

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

बजट का बहीखाता

धन की गति होती है चंचल,
हरदम रहता आता जाता।
लक्ष्मी ही होती नारायणी,
जन-जन का जिससे है नाता।
अब तक जो आते बजट सदा,
उनका ना गणित समझ आता।
अब सबको सदा खबर होगी,
खुल गया देश का बहीखाता।।

सात राज्यों की

13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में 50 से 83 प्रतिशत के बीच मतदान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/एजेन्सी। देश के सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में बुधवार को 50 से 83 प्रतिशत के बीच मतदान हुआ।

बुधवार सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ और मतदान शाम छह बजे तक चला। उपचुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष औ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक प्रबंध किया गया था। जिन सात राज्यों की विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जा रहा उनमें पश्चिम बंगाल की चार, हिमाचल की तीन, उत्तराखंड की दो और मध्य प्रदेश, बिहार पंजाब और तमिलनाडु की एक-एक सीट शामिल है।

उत्तराखंड व पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा

नई दिल्ली/भाषा। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच, सात राज्यों में 13 सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ। मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक था। लोकसभा चुनाव के बाद, पहली बार हो रही चुनावी प्रक्रिया में कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर शामिल हैं। मौजूदा सदस्यों की मृत्यु हो जाने या उनके इस्तीफे के कारण रिक्तियों के चलते ये उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तरांखड और पश्चिम बंगाल को छोड़कर, बाकी राज्यों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट के एक मतदान केंद्र पर प्रतिद्वंद्वी दलों के समर्थकों के बीच झड़प में चार लोग घायल हो गए।

रुड़की सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में बूथ संख्या 53-54 पर दो पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की सूचना मिली थी। कुछ खबरों में दावा किया गया कि मतदान केंद्र पर गोलीबारी भी हुई। हालांकि, पुलिस ने इनका खंडन किया है।

पश्चिम बंगाल की जिन चार सीटों पर बुधवार को मतदान हुआ, उनमें से तीन दक्षिण बंगाल की मानिकतला, रानाघाट दक्षिण और बगदाह सीट तथा चौथी सीट उत्तर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज की है। हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव हैं।

लद्दाख में तस्करी कर लाया गया 108 किलोग्राम सोना जब्त, तीन गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लेह/भाषा। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने भारत-तिब्बत सीमा पर तस्करी कर लाए गए सोने की 108 ईंटे जब्त की हैं और प्रत्येक ईंट का वजन एक किलोग्राम है। केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि सोना के अलावा दो मोबाइल फोन, एक दूरबीन, दो चाकू और कई चीन निर्मित खाद्य सामग्री जैसे केक और दूध भी जब्त की गई है।

उन्होंने बताया, ''आईटीबीपी के इतिहास में उसके द्वारा सोने की यह सबसे बड़ी जब्ती है। जब्त सामग्री को सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है।''

भारत ने दुनिया को 'बुद्ध' दिया, 'युद्ध' नहीं : प्रधानमंत्री मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वियना/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, बल्कि बुद्ध दिया है, जिसका अर्थ है कि उसने हमेशा शांति और समृद्धि दी है और देश 21वीं सदी में अपनी भूमिका मजबूत करेगा। वियना में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी कहा कि भारत आज सर्वश्रेष्ठ होने, सबसे उज्ज्वल बनने और सबसे बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। मोदी ने कहा, ''हम हजारों वर्षों से अपना ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करते रहे हैं। हमने दुनिया को युद्ध नहीं, बल्कि बुद्ध दिया है। भारत ने हमेशा शांति और समृद्धि दी है और इसलिए भारत 21वीं सदी में अपनी भूमिका को और मजबूत करने जा रहा है।''

उन्होंने कहा, ''यह लंबा इंतजार एक ऐतिहासिक अवसर पर समाप्त हुआ है। भारत और ऑस्ट्रिया अपनी दोस्ती के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।'' उन्होंने ''मोदी, मोदी'' के नारों के बीच कहा, ''भौगोलिक दृष्टि से भारत और ऑस्ट्रिया दो अलग-अलग छोर पर हैं, लेकिन हमारे बीच कई समानताएं हैं। लोकतंत्र दोनों देशों को जोड़ता है। स्वतंत्रता, समानता, बहुलवाद और कानून के शासन के प्रति सम्मान हमारे साझा मूल्य हैं। हमारे समाज बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी हैं।

उच्चतम न्यायालय ने सुनाया फैसला

सीआरपीसी की धारा-125 के तहत मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार

- सीआरपीसी की धारा-125 धर्मनिरपेक्ष और धर्म तटस्थ प्रावधान सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे वे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हों।
- भरण-पोषण दान नहीं, बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार है और सभी शादीशुदा महिलाएं इसकी हकदार हैं, फिर चाहे वे किसी भी धर्म की हों।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम महिला आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-125 के तहत अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि सीआरपीसी का यह धर्मनिरपेक्ष और धर्म तटस्थ प्रावधान सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होता है, फिर चाहे वे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हों।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 को धर्मनिरपेक्ष कानून पर तरजीह नहीं मिलेगी। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, हम इस प्रमुख निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज कर रहे हैं कि धारा-125 सभी महिलाओं के संबंध में लागू होगी...।

दोनों न्यायाधीशों ने अलग लेकिन समवर्ती आदेश दिए।

पीठ ने कहा कि पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा-125 के दायरे में मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं। यह धारा पत्नी के भरण-पोषण के कानूनी अधिकार से संबंधित है।

पीठ ने जोर देकर कहा कि भरण-पोषण दान नहीं, बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार है और सभी शादीशुदा महिलाएं इसकी हकदार हैं, फिर चाहे वे किसी भी धर्म की हों। उसने कहा, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 को सीआरपीसी की धारा-125 के धर्मनिरपेक्ष और धर्म तटस्थ प्रावधान पर तरजीह नहीं दी जाएगी।

शीर्ष अदालत ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने गुजारे भत्ते के संबंध में परिवार अदालत के फैसले में दखल देने का समद का अनुरोध ठुकरा दिया था।

समद ने दलील दी थी कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा-125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है और अदालत को मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करना होगा।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील वसीम कादरी की दलीलें सुनने के बाद 19 फरवरी को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

केजरीवाल ने आबकारी घोटाले से मिली रिश्वत का सीधा इस्तेमाल किया : ईडी

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर अपने आरोपपत्र में दावा किया है कि उन्होंने गोवा के एक आलीशान होटल में ठहरकर दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से प्राप्त कथित 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के एक हिस्से का सीधा इस्तेमाल किया। ईडी ने यह भी कहा कि इस संदर्भ में उनकी सरकार द्वारा गठित मंत्रिसमूह 'छलावा' है। एक विशेष धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) अदालत ने 17 मई को दाखिल अभियोजन शिकायत पर को संज्ञान लिया और आम आदमी पार्टी के संयोजक को 12 जुलाई को पेश होने के लिए वारंट जारी किया।

'लोको पायलट' का मनोबल गिराने के लिए विपक्ष कर रहा है दुष्प्रचार : अश्विनी वैष्णव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि 'लोको पायलट' रेलवे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं लेकिन विपक्ष उनका मनोबल गिराने के लिए काफी दुष्प्रचार एवं नाटक कर रहा है। वैष्णव ने 'एक्स' पर ट्रेन चालकों की कार्यदशा सुधारने के लिए रेलवे द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, '' लोको पायलट की ड्यूटी के घंटे पर सावधानीपूर्वक नजर रखी जाती है। यात्राओं (फेरों) के बाद ध्यानपूर्वक उन्हें आराम प्रदान किया जाता है। ड्यूटी के औसत घंटे निर्धारित घंटों (समय सीमा) के अंदर बनाकर रखे जाते हैं।'' उन्होंने कहा, '' इस साल जून माह में (ड्यूटी की) औसत अवधि आठ घंटे से कम रही। आकस्मिक परिस्थितियों में यात्रा अवधि निर्धारित घंटों से अधिक हो जाती है।''

पिछले सप्ताह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 'लोको पायलट' के एक समूह के साथ बैठक की थी। इन 'लोको पायलट' ने ''कम कर्मियों की वजह से पर्याप्त आराम नहीं मिलने'' की शिकायत की थी। गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह संसद में उनके मुद्दे उठायेंगे।

वैष्णव के अनुसार ये 'पायलट' 'लोको कैब' से अपना इंजन (लोकोमोटिव) चलाते हैं तथा 2014 से पहले ये 'कैब' बहुत बुरी दशा में थे। उन्होंने कहा, '' 2014 के बाद 'आरामदायक सीट' के साथ इन 'कैब' में सुधार किया गया। अभी 7000 से अधिक 'लोको कैब' वातानुकूलित हैं।

रणनीतिक साझीदारी के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाएंगे भारत-ऑस्ट्रिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

यूक्रेन युद्ध के 'शांतिपूर्ण समाधान' के लिए किसी भी सामूहिक प्रयास के पक्षधर भारत और ऑस्ट्रिया

वियना/भाषा। भारत और ऑस्ट्रिया ने बुधवार को यूक्रेन संघर्ष के अंतरराष्ट्रीय कानून व संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान के लिए किसी भी सामूहिक प्रयास का समर्थन किया और कहा कि इस पूर्वी यूरोपीय देश में व्यापक तथा स्थायी शांति कायम करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के बीच यहां हुई बातचीत के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने यूरोप के साथ-साथ पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की गहन समीक्षा की। दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति व समृद्धि में योगदान देने के लिए भारत और ऑस्ट्रिया जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर काम करने के महत्व को रेखांकित किया।

विएना/एजेन्सी। भारत एवं ऑस्ट्रिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक दिशा प्रदान कर आर्थिक, शैक्षणिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देने का आज फैसला किया तथा इसके साथ ही दोनों देशों ने यूक्रेन में युद्धविराम एवं शांति स्थापित करने के लिए मिल कर काम करने का संकल्प जताया।

विएना की यात्रा पर मंगलवार को यहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के बीच यहां चांसलरी भवन में आयोजित द्विपक्षीय शिखर बैठक में दोनों देशों के बीच के रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उल्लेखनीय है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यात्रा 41 साल बाद हो रही है।

बैठक के बाद मोदी ने अपने प्रेस वक्तव्य में कहा, मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। इकतालीस साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, लोकतंत्र और कानून का राज जैसे मूल्यों में साझा विश्वास, हमारे संबंधों की मजबूत नींव हैं। आपसी विश्वास और समान हितों से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मज़बूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को रणनीतिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। बुनियादी ढांचे का विकास, नवान्वेषण, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जायेगा । दोनों देशों की युवा शक्ति और विचारों को कनेक्ट करने के लिए स्टार्ट अप ब्रिज को गति दी जायेगी। आवाजाही और आव्रजन साझीदारी पर पहले से समझौता हुआ है।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ भारत में निवेश को लेकर उत्साहित : गोयल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि चार सदस्यीय यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) भारत में निवेश को लेकर उत्सुक है और घरेलू उद्योग को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। भारत और ईएफटीए ने 10 मार्च को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत समूह ने भारत में 15 साल में 100 अरब डॉलर के निवेश को लेकर प्रतिबद्धता जतायी है। साथ स्विस घड़ियां, चॉकलेट और तराशे गये हीरों पर कम या शून्य शुल्क पर सहमति जतायी गयी।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य आइसलैंड, लिसटेंस्टिन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं। गोयल ने कहा कि वह ईएफटीए प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने के लिए रविवार को स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह 100 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए है न कि पोर्टफोलियो निवेश के लिए।

गोयल ने यहां उद्योग के कार्यक्रम में कहा, ''इतिहास में पहली बार, एक एफटीए में निवेश और नौकरियों की बात कही गयी है। यदि वे (ईएफटीए) निवेश प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं, भारत एफटीए में दी गई रियायतें वापस ले सकता है।'' उन्होंने कहा, ''ईएफटीए में मुझे जो उत्साह मिल रहा है, उससे मुझे भरोसा है कि अगर हम सब आगे आएं तो वास्तव में जतायी गयी प्रतिबद्धताओं से

आगे निकल सकते हैं...।'' दोनों पक्षों के बीच व्यापार समझौते के प्रावधानों के अनुसार, यदि चार देशों का समूह 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता हैं, तो भारत के पास ईएफटीए देशों के सामान पर सीमा शुल्क छूट को अस्थायी रूप से वापस लेने का विकल्प होगा। ये निवेश 15 साल में होने हैं। समझौते के क्रियान्वयन के बाद पहला 50 अरब डॉलर का निवेश 10 साल में जबकि शेष अगले पांच साल में होगा। व्यापार समझौते में दायित्वों को पूरा करने के लिए समूह को तीन साल की मोहलत भी दी गयी है।

गोयल ने देश के निर्यात के बारे में कहा कि 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को 2,000 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य हासिल करने लायक है।

उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि की गति को देखते हुए, भारत लगभग चार वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मंत्री ने उद्योग से अनुपालन बोझ को और कम करने पर विचार साझा करने का भी सुझाव दिया। गोयल ने यह भी कहा कि भारत और ब्रिटेन प्रस्तावित द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने संवादादाताओं से कहा कि ब्रिटेन की नई सरकार के जो शुरुआती बयान आये हैं, वे काफी उत्साहजनक हैं। ब्रिटेन के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री कीअर स्टॉर्मर ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात की। उन्होंने कहा कि वह एक एफटीए को अमलीजामा पहनाने को तैयार हैं। यह दोनों पक्षों के लिए काम करेगा। दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभदायक भारत-ब्रिटेन एफटीए के जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुंचाने की दिशा में काम करने पर सहमति जतायी।

चार सरकारी बैंकों ने सरकार को 6,481 करोड़ रुपए का लाभांश दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केनरा बैंक और इंडियन बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 6,481 करोड़ रुपये के लाभांश चेक सौंपे।

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, ''वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) देबदत्त चंद से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,514.22 करोड़ रुपये का लाभांश चेक प्राप्त हुआ।'' इसी तरह, केनरा बैंक के एमडी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सत्यनारायण राजू ने 1,838.15 करोड़ रुपये का लाभांश चेक सौंपा। चेन्नई स्थित इंडियन बैंक ने भी पिछले वित्त वर्ष के लिए सरकार को 1,193.45 करोड़ रुपये का लाभांश चेक दिया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने भी वित्त मंत्री को 935.44 करोड़ रुपये का लाभांश दिया। बैंक के एमडी एवं सीईओ रजनीश कर्नाटक ने इस राशि का चेक सौंपा। इनके अलावा मुंबई स्थित वित्तीय संस्थान एक्जिम बैंक ने भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 252 करोड़ रुपये का लाभांश चेक सरकार को दिया।

जम्मू-कश्मीर के घने जंगलों में आतंकवादियों की तलाश जारी, 24 लोग हिरासत में

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हुए हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाश अभियान बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कम से कम 24 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। इस हमले में सेना के पांच जवान शहीद हो गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि कठुआ के अलावा चार जिलों के घने जंगलों में रुक-रुककर हो रही भारी बारिश के बीच सेना और पुलिस का तलाश अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि यह अभियान तीन अलग-अलग इलाकों- कठुआ, उधमपुर और भद्रवाह से शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने घात लगाकर किए गए हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए 24 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि माना जा रहा है कि आतंकी जंगल में छिपे हैं और उन्हें पकड़ने या फिर मार गिराने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि डोडा जिले के ऊंचे इलाकों में एक और तलाश अभियान जारी है, जहां कठुआ में घात लगाकर किए गए हमले के एक दिन बाद मंगलवार शाम आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। कठुआ में घात लगाकर किए गए हमले से संबंधित तलाश अभियान के बारे में अधिकारियों ने बताया कि उधमपुर, सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों के घने जंगलों के विभिन्न भागों में सेना एवं पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है।

'विकसित भारत' का खाका पेश कर सकता बजट : रिपोर्ट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने पेश किये जाने वाले बजट में 2047 तक 'विकसित भारत' के लिए खाका और राजकोषीय मजबूती के लिए मध्यम अवधि की योजना पेश कर सकती हैं। वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टेनले ने बुधवार को एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। रिपोर्ट में कहा गया, ''राजकोषीय सूझ-बूझ वाले रुख के साथ हमारा अनुमान है कि राजस्व व्यय के मुकाबले पूंजीगत खर्च पर जोर बना रहेगा। साथ ही भौतिक, सामाजिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच में सुधार के साथ लक्षित सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा।''

सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी। ब्रोकरेज कंपनी ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के 5.1 प्रतिशत पर बना रहेगा। यह अंतरिम बजट में तय लक्ष्य के अनुरूप है। साथ ही सरकार अगले वित्त वर्ष तक इसे 4.5 प्रतिशत पर लाने के लक्ष्य पर कायम रहेगी। वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.6 प्रतिशत था। रिपोर्ट के अनुसार, ''भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अपेक्षा से अधिक लाभांश मिलने के साथ राजकोष के मोर्चे पर गुंजाइश बेहतर हुई है। इससे पूंजीगत व्यय की गति बनाये रखने और लक्षित कल्याणकारी उपायों पर खर्च बढ़ाने में मदद मिलेगी।'' ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि इसके साथ कर और गैर-कर राजस्व बेहतर रहने की संभावना को देखते हुए राजकोषीय घाटा लक्ष्य थोड़ा कम यानी 5.1 प्रतिशत से कम हो सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह भी उम्मीद है कि बजट में 2047 तक 'विकसित भारत' के लिए रूपरेखा पर विशेष रूप से ध्यान होगा।

छापेमारी में सुक्खू के विश्वासपात्रों के परिसरों से अभियोजन योग्य सामग्री बरामद : भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

शिमला/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग ने हाल ही में की गई छापेमारी में अभियोजन योग्य दस्तावेज बरामद किए हैं तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दो करीबी करोड़ों रुपये के घोटाले में शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में ईडी और आयकर विभाग के अधिकारियों ने 29 जून तथा चार जुलाई को कुछ व्यापारियों और ठेकेदारों के प्रतिष्ठानों एवं घरों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसियों ने आभूषण की दुकानों, पेट्रोल पंपों और क्रशर पर छापेमारी कर दस्तावेज एकत्र किए। भाजपा नेताओं ने बयान में आरोप लगाया ईडी ने बड़े पैमाने पर ''अवैध खनन'' के संबंध में कुछ निष्कर्ष निकाला है और पाया है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के ''करीबी विश्वासपात्र ज्ञान चंद तथा प्रताप चंद'' करोड़ों रुपये के 'घोटालों' में शामिल हैं। बयान में कहा गया कि ईडी को एक ही खाते में आठ करोड़ रुपये नकद जमा होने के सबूत मिले हैं और ऐसा लगता है कि सरकार ने खुले तौर पर उनका पक्ष लिया तथा राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सात दिनों के भीतर शंभू सीमा खोलने का आदेश दिया

चंडीगढ़/भाषा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को अंबाला के निकट शंभू सीमा पर लगाए गए अवरोधक एक सप्ताह के भीतर हटाने का बुधवार को आदेश दिया। किसान 13 फरवरी से शंभू सीमा पर डेरा डाले हुए हैं, जब उनके 'दिल्ली चलो' मार्च को रोक दिया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली कूच करने की घोषणा की थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोधक लगा दिए थे। अदालत का यह निर्देश, किसानों से जुड़े मुद्दों तथा पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा बंद करने के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक समूह पर आया है। यह निर्देश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति विकास बहल की खंडपीठ ने जारी किया। इस बीच, किसानों ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 16 जुलाई को बैठक बुलाई है। सुनवाई के बाद, हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अदालत ने राज्य सरकार को सात दिनों के भीतर अवरोध हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़ी स्थिति उत्पन्न होने पर यह कानून के अनुसार एहतियाती कार्रवाई कर सकती है। सभरवाल ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब सरकार को भी इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही पंजाब की तरफ अगर कोई अवरोधक लगाया गया था तो उसे भी हटाने को कहा गया है। राजमार्ग खोलने का आदेश दिया गया है। एसकेएम (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च का नेतृत्व किया था।

राज्यों के समक्ष आने वाली समस्याओं के व्यावहारिक समाधान की जरूरत: नीति आयोग सदस्य

नई दिल्ली/भाषा। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने राज्यों के समक्ष आ रही समस्याओं का ''व्यावहारिक'' समाधान ढूंढने की बुधवार को वकालत की। उन्होंने कहा कि राजस्थान तथा ओडिशा जैसे राज्यों ने विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त किए बिना भी अच्छा प्रदर्शन किया है। विरमानी ने कहा कि लोकतंत्र में विशिष्ट समस्याओं को पहचानना और व्यावहारिक समाधान ढूंढने की जरूरत होती है।

वह बिहार और आंध्र प्रदेश को 'विशेष श्रेणी का दर्जा' (एससीएस) दिए जाने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। विरमानी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, '' ऐसी समितियां और आयोग हैं जिन्होंने (राज्यों के लिए) विशेष राज्य के दर्जे के लिए मानदंड निर्धारित करने का प्रयास किया है। यह एक जटिल मुद्दा भी है।'' अर्थशास्त्री ने कहा कि पिछले 30-40 वर्षों में '' हमारे यहां 'बीमारू' राज्य हुआ करते थे।'' उन्होंने कहा, '' मिसाल के तौर पर ओडिशा ने बहुत विकास किया है, राजस्थान ने भी बहुत प्रगति की है और चीजें बदल गई हैं। जहां तक मुझे पता है, इनमें से किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं मिला है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है।''

तस्कर को 100 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया गया

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली पुलिस ने शाहदरा क्षेत्र में कई लुप्तप्राय प्रजातियों के कछुओं समेत 100 कछुओं की तस्करी करने के आरोप में 38 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गाजियाबाद निवासी भीम के कब्जे से 50 'इंडियन रुफड टर्टल', 45 'ब्लैक स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल', तीन 'इंडियन आई टर्टल' और दो इंडियन सॉफ्टशेल टर्टल' बरामद किए गए हैं। 'ब्लैक स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल', 'इंडियन आई टर्टल' और 'इंडियन सॉफ्टशेल टर्टल' लुप्तप्राय प्रजातियों में से हैं जो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-ख के अंतर्गत आते हैं। पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) सुरेंद्र चौधरी ने बताया, मंगलवार को गीता कॉलोनी थाना पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में लुप्तप्राय प्रजाति के कछुओं के साथ एक तस्कर आया है।

वेदांता के कारोबार विभाजन के प्रयास जारी, छह नई कंपनियों का गठन होगा : अग्रवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि कंपनी अपने विभिन्न कारोबार को अलग करने की योजना पर आगे बढ़ रही है, जिससे छह नई कंपनियां बनेंगी और व्यापक मूल्य हासिल किया जा सकेगा। वेदांता को अपने कारोबार को अलग करने की योजना के लिए ज्यादातर कर्जदाताओं से मंजूरी मिल गई है। यह कंपनी को छह स्वतंत्र सूचीबद्ध कंपनियों में विभाजित करने की योजना के लिए एक अहम कदम है।

अग्रवाल ने वेदांता के शेयरधारकों की 59वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ''हम कारोबार को अलग करने की योजना पर आगे बढ़ रहे हैं। इससे छह सशक्त कंपनियों का निर्माण होगा जिनमें से प्रत्येक अपने-आप में वेदांता होगी। इससे बड़े पैमाने पर मूल्य हासिल होगा।'' अलग होने वाली प्रत्येक इकाई अपनी योजना खुद बनाएगी, लेकिन वेदांता के मूल मूल्यों, इसकी उद्यमशीलता की भावना और वैश्विक नेतृत्व का अनुसरण करेगी। अग्रवाल ने कहा, ''हम एक अद्भुत बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं, लिहाजा हमारा जोश चरम पर है। यह विभाजन हमारे सफर को रफ्तार देगा।'' वेदांता ने सितंबर, 2023 में धातु, बिजली, एल्युमीनियम और तेल एवं गैस कारोबार को अलग करने की घोषणा की थी। इस तरह छह स्वतंत्र कंपनियां- वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटीरियल्स, वेदांता बेस मेटल्स और वेदांता लिमिटेड बनाई जाएंगी। चेयरमैन ने कहा कि हरेक इकाई को पूंजी आवंटन और उनकी वृद्धि रणनीतियों के संबंध में अधिक स्वतंत्रता होगी। इससे निवेशकों को अपनी पसंद के उद्योगों में निवेश करने की स्वतंत्रता होगी जो वेदांता परिसंपत्तियों के लिए समग्र निवेशक आधार बढ़ाने का काम करेगा।

उन्होंने कहा, ''शेयरधारकों के पास फिलहाल वेदांता लि. के जितने शेयर हैं, उनमें से प्रत्येक शेयर पर उन्हें पांचों नई सूचीबद्ध कंपनियों का एक-एक शेयर अतिरिक्त रूप से मिलेगा।''

जुड़वां बेटियों के जन्म से नाराज पिता ने नवजातों की हत्या की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में बेटे की चाह रखने वाले 32 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी तीन दिन की जुड़वां बेटियों की कथित तौर पर हत्या कर दी और उन्हें अपने घर के पास दफना दिया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी ।

पुलिस अधिकरी ने बताया कि आरोपी नीरज सोलंकी को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया गया है । पुलिस उपायुक्त (अपराध) अमित गोयल ने बताया कि स्थानीय लोगों को पूठ कलां गांव के पास एक अस्थायी श्मशान घाट परिसर में शिशुओं के शव मिले। उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक सोलंकी ने तीन जून को अपनी बेटियों की हत्या कर दी थी। गोयल ने कहा, ''अदालत से अनुमति मिलने के बाद शवों को पांच जून को बाहर निकाला गया और मंगोलपुरी स्थित एसजीएम अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया।'' डीसीपी ने बताया कि सोलंकी ने कथित तौर पर अपनी तीन दिन की बेटियों को इसलिए मार डाला क्योंकि वह बेटा चाहता था। बच्चियों का जन्म हरियाणा में एक निजी अस्पताल में हुआ था।

संसद की सुरक्षा औपचारिक रूप से संभालने की तैयारी में सीआईएसएफ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) संसद परिसर की सुरक्षा औपचारिक रूप से संभालने की तैयारी में हैं। इसके 3,300 से अधिक कर्मियों की टुकड़ी को 29 अधिकारियों के साथ औपचारिक रूप से तैनाती की जा रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया 29 अधिकारी 3,317 पुरुष और महिला कर्मियों उस टुकड़ी का नेतृत्व करेंगे, जिसमें एक उप महानिरीक्षक (डीआईजी), एक वरिष्ठ कमांडेंट, दो कमांडेंट, 7 डिप्टी कमांडेंट और 18 सहायक कमांडेंट करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इनमें से दो अधिकारी अग्निशमन

शाखा के हैं क्योंकि बल ने यहां अपनी अग्निशमन इकाई भी तैनात की है। गत मई महीने में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और दिल्ली पुलिस से ये कार्यभार संभालने के बाद से केंद्रीय बल स्वतंत्र रूप से संसद की सुरक्षा कर रहा है। संसद पर 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकी हमले की बरसी पर पिछले साल संसद की सुरक्षा में चूक की घटना सामने आई थी। इसके बाद संसद की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ को तैनात किया गया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान दो व्यक्ति दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर कूद गए थे और कनस्तरों से पीला धुआं छोड़ा था तथा सांसदों द्वारा पकड़े जाने से पहले नारे लगाए थे। उस दिन लगभग उसी समय, दो अन्य लोगों ने संसद परिसर के बाहर नारे लगाते हुए कनस्तरों से रंगीन धुआं छोड़ा था। सूत्रों ने बताया कि इन अधिकारियों को मई-जून से संसद परिसर भवन में सीआईएसएफ की अस्थायी ''आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी पैटर्न'' तैनाती के हिस्से के रूप में पहले से ही तैनात किया गया था, लेकिन इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 22 जुलाई को संसद का अगला सत्र शुरू होने से पहले इस शस्त्र बल को औपचारिक रूप से संसद भवन परिसर की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात किया जाएगा। अन्य अधिकारी ने कहा कि विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस संसद तक जाने वाले मार्गों की निगरानी करेंगे जैसा कि हाल ही में समाप्त हुए सत्र के दौरान किया था।

आदित्य ठाकरे ने बीएमडब्ल्यू 'हिट-एंड-रन मामले में बुलडोजर न्याय' की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

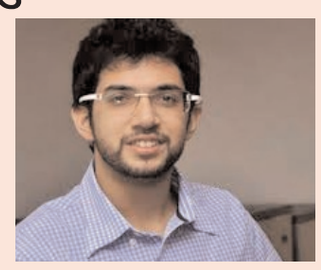

मुंबई/भाषा। शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को मुंबई के बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में 'बुलडोजर न्याय' की मांग की। इस मामले में शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा मुख्य आरोपी है। उन्होंने पूछा कि मामले में दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? पूर्व राज्य मंत्री ने रविवार सुबह दुर्घटना में मारी गई महिला कावेरी नखवा (45) के परिवार से मुलाकात की और जोर देकर कहा कि उनके परिजनों को आर्थिक मदद की नहीं बल्कि न्याय की जरूरत है। मिहिर कथित तौर पर बीएमडब्ल्यू कार चला रहा था जिसने दक्षिण-मध्य मुंबई के वर्ली इलाके में एक दोपहिया वाहन को टक्कर मारी, जिससे कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई थी जबकि उनके पति प्रदीप घायल हो गए।

वर्ली से विधायक ठाकरे ने कहा, जो सरकार बुलडोजर न्याय में विश्वास करती है उसे उनके (आरोपी) घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए। मैं मिहिर राजेश शाह के घर पर 'बुलडोजर न्याय' देखना चाहूंगा। बुलडोजर न्याय का मतलब उन व्यक्तियों की संपत्तियों को शक्तिशाली मोटर चालित मशीनों से ध्वस्त करना है जिन पर गंभीर अपराधों में संलिप्त होने के आरोप हैं। ऐसी कई दंडात्मक कार्रवाई की खबरें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सामने आती रही हैं।

ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया कि बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले को हत्या का मामला माना जाना चाहिए तथा उसके अनुसार ही कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने मृतक महिला के परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की थी। राजेश शाह को शिवसेना के उपनेता पद से बर्खास्त कर दिया गया है।

मिहिर शाह को दुर्घटना के लगभग तीन दिन बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया और वह फिलहाल 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में है।

कुलपतियों, विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को अपने खर्च पर मुकदमा लड़ना होगा : राज्यपाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कन्नूर और कालीकट सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों को अपने निर्देश में कहा है कि इस तरह के मुकदमों में आने वाले कानूनी खर्च के लिए निधि आवंटित करने का फैसला अनुचित और विश्वविद्यालय के धन का दुरुपयोग है...

तिरूवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होने के नाते, यह निर्देश दिया है कि उनके आदेश के खिलाफ वाद दायर करने वाले कुलपतियों और विश्वविद्यालयों के अन्य अधिकारियों को मुकदमे का खर्च खुद वहन करना चाहिए।

खान ने कन्नूर और कालीकट सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों को अपने निर्देश में कहा है कि इस तरह के मुकदमों में आने वाले कानूनी खर्च के लिए निधि आवंटित करने का फैसला अनुचित और विश्वविद्यालय के धन का दुरूपयोग है।

उन्होंने विश्वविद्यालयों से कहा है कि कुलाधिपति या विश्वविद्यालय के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों के कानूनी खर्चों को पूरा करने के वास्ते कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। खान ने नौ जुलाई को विश्वविद्यालयों से कहा, ...यदि ऐसा कोई भुगतान पहले ही किया जा चुका है तो राशि उस अधिकारी से तत्काल वसूल की जाएगी जिसकी ओर से भुगतान किया गया था।

उन्होंने विश्वविद्यालयों को कानूनी खर्च (यदि कोई किया गया हो) के भुगतान के संबंध में लिए गए निर्णयों और रकम वापसी की वर्तमान स्थिति का विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। खबरों के अनुसार, खान द्वारा कुलाधिपति के रूप में जारी किये गए कुछ आदेशों को अदालतों में चुनौती देने में, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने कुलपतियों और विश्वविद्यालयों के अन्य अधिकारियों द्वारा किये गए कानूनी खर्चों पर कई हजार से लेकर लाखों रुपये व्यय किए हैं।

न्यायालय तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर कल करेगा सुनवाई

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। बालाजी को पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा समय मांगे जाने के बाद मामले को स्थगित कर दिया। पीठ ने कहा,'' इसे परसों, 12 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करें।'' बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में ईडी ने कई बार स्थगन लिया है।

शीर्ष अदालत ने एक अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी करते हुए बालाजी की जमानत याचिका पर जवाब मांगा था। इसे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को बालाजी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यदि उन्हें इस तरह के मामले में जमानत पर रिहा किया गया तो इससे गलत संकेत जाएगा और यह व्यापक जनहित के खिलाफ होगा। उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ता आठ महीने से अधिक समय से कारावास में है इसलिए विशेष अदालत को समय सीमा के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश देना अधिक उपयुक्त होगा। बालाजी को पिछले साल 14 जून को धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला नौकरी के लिए नकदी घोटाले से जुड़ा है और उस वक्त बालाजी अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे। ईडी ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ 3000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।

रामनगर जिले का नाम बदलने को लेकर सियासी बवाल, कैबिनेट में प्रस्ताव रखने की तैयारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु। कर्नाटक में रामनगर जिले का नाम बदलने को लेकर सियासी बवाल मच गया है। कर्नाटक सरकार के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सीएम सिद्दरामैया को रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलूरु दक्षिण करने का प्रस्ताव सौंपा है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार (९ जुलाई) को कर्नाटक के रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलूरु दक्षिण जिला करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्दरामैया को दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि नाम बदलने के पीछे उनका उद्देश्य बेंगलूरु की वैश्विक प्रतिष्ठा का उपयोग करना है।

कर्नाटक के सीएम सिद्दरामैया ने कहा कि मैंने सभी प्रभारी मंत्रियों से जिला स्तरीय बैठकें, जनस्पंदन बैठकें आयोजित करने को कहा है। हमने डीसीएस, सीआरओ और सचिवों के साथ दो दिन की बैठक की। रामनगर नाम परिवर्तन मुद्दे पर डीके शिवकुमार के नेतृत्व में रामनगर जिले के नेता मुझसे मिलने आए। उन्होंने इसका नाम बेंगलूरु दक्षिण करने को कहा। मैंने उनसे कहा कि इस पर कैबिनेट को फैसला करना है और मैं कैबिनेट में प्रस्ताव रखूंगा। ईडी छापे पर सीएम सिद्दरामैया ने कहा कि यह उनका काम है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें कानूनी तौर पर अपना काम करने दें। मुझे नहीं पता कि वे बी नागेंद्र को हिरासत में लेते हैं या नहीं। हमने केंद्र को कई प्रस्ताव दिए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और जवाब देंगे। चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं।

एमयूडीए साइट आवंटन में कथित अनियमितताओं के भाजपा के आरोपों पर सीएम ने कहा कि आप यह बात कितनी बार पूछेंगे। हमने घोटाले में शामिल लोगों को निलंबित कर दिया है और जांच चल रही है। हम एमयूडीए में सदस्यों के रूप में प्रतिनिधियों को हटाने का निर्णय लेने पर विचार कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नेता सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्यों? क्या हमारी पुलिस जांच करने में सक्षम नहीं है, मैंने कई मामले सीबीआई को दिए, क्या उन्होंने एक भी मामला सीबीआई को दिया? कर्नाटक पुलिस जांच करने में सक्षम है और कर रही है।

कर्नाटक को जापान, दक्षिण कोरिया की कंपनियों से 6,450 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धता मिली

बेंगलूरु। कर्नाटक ने जापान और दक्षिण कोरिया से 6,450 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धता हासिल की है जिससे 1,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने की संभावना है। राज्य सरकार के मंत्री एम बी पाटिल ने बुधवार को यह जानकारी दी। विशाल एवं मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री पाटिल हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे से लौटे हैं। वह 24 जून से पांच जुलाई तक दोनों देशों की यात्रा पर थे। पाटिल की अगुवाई में यात्रा पर गए प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के उद्योग दिग्गजों से मुलाकात की और लघु एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। पाटिल ने यहां संवाददाताओं को इस दौरे की उपलब्धियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा, हमें 6,450 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धताएं और समझौता ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। छह प्रमुख कंपनियों की इन निवेश प्रतिबद्धताओं से कर्नाटक में 1,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित दो रोड शो में 35 से अधिक उद्योग जगत के दिग्गजों और 200 कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। पाटिल ने कहा कि ओसाका गैस ने अगले पांच वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से कर्नाटक में अपने गैस वितरण बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की प्रतिबद्धता जताई है।

कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र का आरोप, कहा- मुडा घोटाले में शामिल है सिद्दरामैया का परिवार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक में मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) घोटाले को लेकर बीजेपी ने सिद्दरामैया सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने मुदा घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि जो पैसा एससी/एसटी के लिए था, उसका इस्तेमाल कर्नाटक ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के चुनावों में भी किया गया। बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि सीएम सिद्दरामैया के नेतृत्व में 5000 करोड़ से अधिक की साइट आवंटित की गई है। शहरी विकास मंत्री बैराठी सुरेश इस घोटाले में शामिल अधिकारियों को बचा रहे हैं। मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। सीएम सिद्दरामैया खुद मैसूर से हैं और उनकी पत्नी को 30-40 करोड़ से अधिक की साइट अवैध रूप से दी गई।

उन्होंने बताया कि बीजेपी इस घोटाले को लेकर मैसूर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। पिछले साल बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं। इस विभाग में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। सीएम का परिवार खुद इसमें शामिल है और सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इस संबंध में हम सरकार का घेराव भी करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र ने कर्नाटक सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पड़ोसी राज्यों में पैसे भेजे गए हैं और इस पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में किया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पिछले दो महीनों में एसआईटी ने मंत्री बी नागेंद्र को नोटिस जारी करने की जहमत तक नहीं उठाई। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक एसआईटी ने उन्हें पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। इसलिए अब वे जांच को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा वाल्मीकि विकास निगम घोटाले में जांच की मांग कर रही है, क्योंकि यह पैसा दलितों और उनके समुदाय के विकास का है। इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। खुद मंत्री भी इसमें शामिल हैं, शरण प्रकाश पाटिल का नाम भी इस घोटाले में सामने आया है। हम एसआईटी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्दरामैया के मंत्री भी इसमें शामिल हैं।

कर्नाटक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने राहुल गांधी पर टिप्पणी के लिए भाजपा विधायक भरत शेट्टी की आलोचना की

मंगलूरु। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक भरत शेट्टी पर बुधवार को निशाना साधा। भाजपा विधायक ने रविवार को सुरथकल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को 'संसद के अंदर गिरफ्तार कर थप्पड़ मारे जाने चाहिए'।

भाजपा विधायक का यह बयान सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो गया और कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बयान को लेकर मीडिया में व सोशल मीडिया मंचों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष मंजूनाथ भंडारी ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक पर कटाक्ष किया और पूछा, वे संसद में कैसे प्रवेश करेंगे? क्या वह नेता विपक्ष पर हमला करने के लिए हथियार लेकर जाएंगे? क्या शेट्टी आतंकवादी हैं? उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि भरत शेट्टी कांग्रेस पार्टी के एक आम कार्यकर्ता से सीधे बात भी नहीं कर सकते और राहुल गांधी से भिड़ना तो दूर की बात है। भंडारी ने भाजपा नेताओं और विधायकों के राहुल गांधी पर भड़कने का मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कांग्रेस नेता को 'बालक बुद्धि' करार दिया जाना बताया। उन्होंने कहा कि इस शब्द को सदन की कार्यवाही से 'हटाया' जाना चाहिए। भंडारी ने कहा कि हाल के दिनों में दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा विधायकों के व्यवहार के कारण 'हमें तटीय क्षेत्र से विधायक चुनने में शर्म आ रही है।' उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य में कांग्रेस सरकार की उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रही है इसलिए वह दंगों की साजिश रच रही है।

मुडा घोटाला: मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की भाजपा की मांग खारिज की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामैया ने मुआवजे के तौर पर मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) द्वारा भूखंड आवंटित करने में कथित फर्जीवाड़े की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मांग को बुधवार को खारिज कर दिया। भाजपा का आरोप है कि मुडा ने उन लोगों को मुआवजे के तौर पर भूखंड वितरित करने में अनियमितता बरती जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। मुआवजे के तौर पर भूखंड प्राप्त करने वालों में सिद्दरामैया की पत्नी समेत पार्वती भी शामिल हैं। सिद्दरामैया ने भाजपा पर ऐसी बात का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया, जो कोई मुद्दा ही नहीं है।

भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष वी. वाई. विजयेंद्र ने दिन में कहा था कि मुडा द्वारा जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उन्हें भूखंड आवंटित करने में कथित फर्जीवाड़ा करने के खिलाफ 12 जुलाई को सिद्दरामैया के गृह जिले मैसुरु में 'विशाल' विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा ने आरोप लगाया कि पार्वती को मैसुरु के एक 'पॉश' इलाके में मुआवजे के तौर पर ऐसा भूखंड आवंटित किया गया जिसका मूल्य उनकी उस जमीन की तुलना में अधिक था जिसका मुडा ने अधिग्रहण किया था। मुडा ने पार्वती को उनकी तीन एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की जमीन के बदले में 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे। इस विवादास्पद योजना के तहत अधिग्रहीत अविकसित भूमि के बदले में भूमि देने वाले को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित करने की परिकल्पना की गई है। सिद्दरामैया ने यहां संवाददाताओं से कहा, दो मुद्दे हैं, एक तो यह है कि अक्टूबर में ही मुडा को 50:50 अनुपात वाली योजना के तहत जगह नहीं देने को कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें दी गयी, जिसकी जांच दो आईएएस अधिकारी कर रहे हैं और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, वे (भाजपा) मेरी पत्नी को दी गई जगह को मुद्दा बनाना चाहते हैं, यह कोई मुद्दा ही नहीं है।

उन्होंने कहा, क्या हमने विजयनगर में जमीन दिए जाने की मांग की थी? हमने नहीं की थी। हमारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। अगर आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप दावा नहीं करेंगे? इस मामले में यही हुआ है। हमने अपनी जमीन के लिए मुआवजा मांगा था और उन्होंने (मुडा ने) विजयनगर में जमीन दी और उन्होंने बैठक में स्वीकार किया कि हमारी जमीन का अवैध रूप से अधिग्रहण किया गया जो गलत था। मुख्यमंत्री ने भाजपा के प्रस्तावित विरोध को राजनीतिक करार देते हुए कहा कि अगर वे विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हैं, तो हम इसका जवाब देंगे। उन्होंने भाजपा द्वारा सीबीआई जांच की मांग किए जाने पर कहा, क्या हमारी पुलिस जांच नहीं कर सकती? हमारी पुलिस किस लिए है? मैंने अपनी सरकार के दौरान सीबीआई को कई मामले सौंपे हैं, क्या उन्होंने (भाजपा ने) सत्ता में रहते हुए कोई मामला सौंपा? सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद कर्नाटक में डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) थे, हमारी पुलिस जांच करने की काबिलियत रखती है।

मुडा 'घोटाला' : भाजपा मुख्यमंत्री के गृह जिले में 12 जुलाई को करेगी 'विशाल' विरोध प्रदर्शन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) द्वारा जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उन्हें भूखंड आवंटित करने में कथित फर्जीवाड़ा करने के खिलाफ 12 जुलाई को मुख्यमंत्री सिद्दरामैया के गृह जिले मैसुरु में 'विशाल' विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.वाई.विजयेंद्र ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने ने दावा किया कि मुख्यमंत्री सिद्दरामैया की पत्नी पार्वती को भी भूखंड आवंटित किया गया है और उनसे इस मुद्दे पर इस्तीफा देने की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदर्शनकारी अवैध तरीके से किए गए आवंटन को रद्द करने और उक्त जमीन गरीबों को आवंटित करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी इस 'घोटाले'की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग कर रही है क्योंकि आरोप स्वयं मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर लगा है। विजयेंद्र ने घोषणा की कि भाजपा आगामी विधान मंडल सत्र में भी यह मुद्दा उठाएगी। पार्टी ने आरोप लगाया कि किसानों को मैसुरु के संभ्रांत इलाके में मुआवजे के तौर पर दी जाने वाली जमीन सिद्दरामैया की पत्नी को आवंटित की गयी जिसकी कीमत मुडा द्वारा 'अधिग्रहित'उनकी जमीन से अधिक है। मुडा ने पार्वती की अधिग्रहित 3.16 करोड़ रुपये की जमीन के एवज में 50:50के अनुपात में जमीन आवंटित की और उक्त जमीन पर उसने आवासीय इमारते बनाने की योजना बनाई है।

मुडा के कथित 'घोटाले'के बारे में विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जनता को गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री का असली चेहरा सभी के सामने आ गया है। इस भूमि घोटाले के प्रत्येक चरण में अनियमितताएं की गई हैं। विजयेंद्र ने कहा, मुख्यमंत्री को जनता को जवाब देना चाहिए और घोटाले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए...मुख्यमंत्री ने गरीब महिलाओं को 2000 रुपये महीना देने का वादा किया था और उन्होंने अपनी पत्नी को दो-दो करोड़ मूल्य के 14 भूखंड दिए हैं जिनकी कीमत 63-64 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा, देश में अगर कोई मुख्यमंत्री है जिसने अपने कार्यकाल में अनियमितताएं की और अपनी ही सरकार से मुआवजा मांगा तो वह सिद्दरामैया हैं। विजयेंद्र ने रेखांकित किया कि मुडा ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए पार्वती को 14 भूखंड आवंटित किये। उन्होंने कहा लेकिन अधिनियम के तहत अगर तीन से चार एकड़ जमीन अधिग्रहीत की जाती है तो अधिग्रहीत जमीन के बदले 40 गुना 60 फुट के केवल दो भूखंड दिए जाने चाहिए।

ईडी को अपना काम करने दें : वाल्मीकि निगम 'घोटाला' मामले में छापेमारी पर सिद्दरामैया ने कहा

मैसूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामैया ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितता संबंधी ईडी की जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय चार राज्यों में छापेमारी कर रहा है जिनमें सिद्दरामैया सरकार के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र और कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक बसनगौड़ा दद्दाल के परिसर भी शामिल हैं जो संबंधित निगम के अध्यक्ष हैं। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व एक अन्य राज्य में करीब 20 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की यह छापेमारी धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में हो रही है।

छापेमारी संबंधी एक सवाल के जवाब में सिद्दरामैया ने कहा, ईडी को अपना काम करने दें। हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्हें कानून के अनुसार अपना काम करने दें, उन्हें जो करना है, उन्हें करने दें। निगम से संबंधित अवैध धन हस्तांतरण का मामला तब प्रकाश में आया जब इसके लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन पी ने 26 मई को आत्महत्या कर ली। चंद्रशेखरन ने सुसाइड नोट में निगम के बैंक खाते से 187 करोड़ रुपये के अनधिकृत हस्तांतरण का दावा किया था। उन्होंने निगम के अब निलंबित प्रबंध निदेशक जे जी पद्मनाभ, लेखा अधिकारी परशुराम जी दुरुगनवर और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य प्रबंधक सुचिस्मिता रावल का नाम लिया था।

राहुल गांधी पर टिप्पणी करने वाले भाजपा विधायक भरत शेट्टी पर मामला दर्ज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मंगलूरु। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक भरत शेट्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंगलूरु शहर पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने यहां संवाददाताओं को बताया कि मंगलुरु नगर निगम के कांग्रेस पार्षद के. अनिल द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद कवूर थाने में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। कांग्रेस पार्षद ने शिकायत में आरोप लगाया कि विधायक भरत शेट्टी ने राहुल गांधी का नाम लेते हुए एक भड़काऊ बयान दिया था। अग्रवाल ने कहा कि मामले की जांच जारी है।

इस बीच, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करने को लेकर भाजपा विधायक शेट्टी पर निशाना साधना जारी रखा। भाजपा विधायक ने रविवार को सुरथकल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कथित तौर पर कहा था कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को संसद के अंदर गिरफ्तार कर थप्पड़ मारे जाने चाहिए। विधायक का यह बयान सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो गया और कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बयान को लेकर मीडिया व सोशल मीडिया मंचों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष मंजूनाथ भंडारी ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक पर कटाक्ष किया और पूछा, वे संसद में कैसे प्रवेश करेंगे? क्या वह नेता विपक्ष पर हमला करने के लिए हथियार लेकर जाएंगे? क्या शेट्टी आतंकवादी हैं? उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि भरत शेट्टी कांग्रेस पार्टी के एक आम कार्यकर्ता से सीधे बात भी नहीं कर सकते और राहुल गांधी से भिड़ना तो दूर की बात है। भंडारी ने भाजपा नेताओं और विधायकों के राहुल गांधी पर भड़कने का मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कांग्रेस नेता को बालक बुद्धि करार दिया जाना बताया।

न्यायालय ने अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नयी दिल्ली/बेंगलूरु। उच्चतम न्यायालय ने जनता दल (सेक्यूलर) के निलंबित नेता और दुष्कर्म के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अपहरण के एक मामले में दी अग्रिम जमानत रद्द करने से बुधवार को इनकार कर दिया। यह उनके बेटे के कथित यौन शोषण की पीड़िताओं में से एक के अपहरण का मामला है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कर्नाटक सरकार की अपील पर भवानी रेवन्ना को नोटिस जारी किया। पीठ ने कर्नाटक सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, आरोपी एक महिला है जिसकी उम्र 55 वर्ष है। उनके बेटे पर घिनौने कामों में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। वह भाग गया था और आखिरकार उसे पकड़ लिया गया।

उन्होंने कहा, इस तरह के आरोपों के मामले में अपने बेटे द्वारा किए अपराधों को बढ़ावा देने में मां की क्या भूमिका होगी? सिब्बल ने

कहा कि भवानी रेवन्ना को दी गयी राहत बेहद दुखद है और परिवार के इशारे पर ही पीड़िता को बंधक बनाकर रखा गया था। इस पर पीठ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है...इस मामले का राजनीतिकरण न करें।

उच्च न्यायालय ने 18 जून को भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत देते हुए कहा था कि उन्होंने पूछताछ के दौरान 85 सवालों के जवाब दिए हैं जिससे यह दावा करना उचित नहीं है कि वह एसआईटी के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं। एसआईटी उनके बेटे के खिलाफ यौन शोषण के मामलों की जांच कर रही है। एसआईटी ने मैसुरू जिले के के.आर. नगर में एक घरेलू सहायिका के अपहरण के सिलसिले में पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होने के बाद भवानी की हिरासत का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने का अनुरोध करने वाली भवानी रेवन्ना की याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि इस मामले में 'मीडिया ट्रायल' से बचा जाना चाहिए। उसने कहा था कि महिलाओं की अनावश्यक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे परिवारों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। अदालत ने यह भी कहा था कि असहयोग के आरोप अविश्वसनीय थे क्योंकि भवानी ने पूछताछ के दौरान पहले ही विस्तृत जवाब दे दिए थे। न्यायालय ने एसआईटी की इस दलील को खारिज कर दिया कि उन्होंने भ्रामक जवाब दिए थे। अदालत ने सात जून को भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत देते हुए उन पर मैसुरु और हासन जिलों में प्रवेश करने से रोक लगाने की शर्तें लगायी थीं तथा बाद में जमानत अवधि 14 जून तक बढ़ा दी थी।

भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट किया पेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भजन लाल सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। जिसमें वर्ष 2024-25 का राजकोषीय घाटा 70 हजार 09 करोड़ 47 लाख है जो जीएसडीपी का 3.93 प्रतिशत है जबकि बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 25 हजार 758 करोड़ 11 लाख रुपए हैं।

उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य सरकार के परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 को सदन में पेश किया जिसमें वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में दो लाख 64 हजार 461 करोड़ 29 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां एवं वर्ष 2024-25 मे बजट अनुमानों में दो लाख 90 हजार 219 करोड़ 40 लाख रुपए का राजस्व व्यय है। श्रीमती दीया कुमारी ने पूर्वाह्न ग्यारह बजकर एक मिनट पर बजट भाषण पढ़ने शुरु किया जो एक बजकर 52 मिनट पर समाप्त हुआ। बजट में चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं वहीं कई घोषणाएं भी की गई। इसमें सीएनजी एवं पीएनजी पर प्रचलित वेट दर को 14.5 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया गया हैं। पत्नी , पुत्रवधू , पोता, पोती एवं दोहिता, दोहिती के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर स्टाम्प डॅयूटी एवं पंजयीन शुल्क पर पूरी छूट दी गई हैं।

इसी तरह परिवार के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व के अधीन दो या अधिक गैर कृषि संपत्तियों के बदलने पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर दो प्रतिशत की गई हैं। सैनिकों एवं अर्द्धसैनिक बलो के शहीदों की वीरांगनाओं, उनके पुत्र , पुत्री या माता पिता को सरकार , निजी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा निशुल्क आवास दिय जाने पर स्टाम्प डॅयूटी के साथ ही पंजीयन शुल्क की भी छूट दी गई हैं। निर्माणाधीन प्लैटस एवं भवनों पर जीएसटी राशि पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट का प्रावधान किया है।

राज्य में रवीन खनिज नीति 2024 लाई जायेगी। राजस्व संग्रहण में निपुणता लाने तथा अवैध मदिरा पर अंकुश लगाने की दृष्टि से नया आबकारी कानून लाया जायेगा। बलुआ पत्थर , चेजा पत्थर आदि में खिनजों में एक हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों की नीलामी में सिक्योरिटी राशि दस लाख रुपए से घटाकर दो लाख रुपए की गई हैं। इसी तरह रीको एरिया से एक किलोमीटर परिधि में भी भूमि रुपातंरण के लिए रीको की अनापत्ति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और निजी औद्योगिक पार्क योजना भी लाई जायेगी। रीको को हस्तांतरित औद्योगि क्षेत्रों के रुपान्तरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए ट्रांसफर आफ इंडस्ट्रियल लेंड्स वेलिडेशन एक्ट लाया जायेगा। वहीं15 मीटर की ऊंचाईतक के भवनों के फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए निर्धारित एक मुश्त फीस 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर को घटाकर 15 रुपए प्रति वर्गमीअर पांच वर्ष के लिए की गई हैं।

इसी तरह पेयजल में जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य एवं लगभग 20 हजार 370 करोड़ रुपये की लागत से छह वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य किया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में आगामी दस वर्षो में प्रदेश में विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्ययोजना के तहत हर घर हर खेत बिजली निर्बाध रुप से उपलब्ध कराने का संकल्प , पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक में आदर्श सौर ग्राम एवं सभी राजकीय कार्यालयों को भी समयबद्व रुप से सौर ऊर्जा से जोड़ना है।

राज्य में सड़कों के लिए पांच वर्षो में 53 हजार किलोटर लम्बाई का सड़क नेटवर्क पर लगभग 60 हजार रुपये का व्यय किया जाएगा एवं क्षतिग्रस्त एक हजार 343 सड़को एवं पुलियाओं की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य एवं दो वर्षो में 644 करोड़ रुपये किए जायेंगे। क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधाएं में डा.श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास से प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन नीति , बालोतरा में राजस्थान पेट्रो जोन , भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क, बीकानेर में सिरामिक पार्क बनायें जायेंगे।

राज्य में पर्यटन , कला एवं संस्कृति क्षेत्र में नवीन पर्यटन नीति , राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन , जयपुर , जोधपुर , उदयपुर , भरतपुर , सवाई माधोपुर , एवं पुष्कर सहित 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य करायें जायेंगे। वन एवं पर्यावरण क्षेत्र में आगामी वर्ष से राज्य में ग्रीन बजट , वृक्षारोपण महाभियान के माध्यम से सात करोड़ पौधे लगाने एवं पालने का लक्ष्य , दो हजार वन मित्र एवं पांच बाघ परियोजना क्षेत्रों में 20 करोड़ रुपये की राशि से टाइगर हैबिटेट सुधार के कार्य एवं अलवर में जैविक पार्क पर 25 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह बजट में युवा विकास एवं कल्याण क्षेत्रों में पांच वर्षो में चार लाख भर्तियां में इस वर्ष एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती , युवा नीति-2024 में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में कौशल उन्नयन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर , विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी देने का प्रावधान किया गया है। 12 नये महाविद्यालय , आठ कन्या महाविद्यालय, तीन कृषि महाविद्यालय एवं दस महाविद्यालयों का यूजी से पीजी में क्रमोन्नत किया जायेगा। स्टेट स्किल पोलिसी केतहत दो वर्षो में एक लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। बीस संस्कृत महाविद्यालयों के लिए भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए व्यय किये जायेंगे।

सामाजिक सुरक्षा के लिए एससीएसपी एवं टीएसपी फंड की राशि बढ़ाकर एक हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को 25 हजार रुपए अतिरिक्त अनुदान, स्थाई आश्रय और आवास से वंचित डिनोटिफाइड ट्राइब्स के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री घुमन्तू आवासीय योजना ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया हैं।

दिव्यांगों की सुविधा के लिए दिव्यांग को 20 हजार रुपए तक के उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे 50 हजार दिव्यांग लाभांवित होंगे। इसी तरह गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए राहत पैकेज के तहत प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की राशि से रेयर डिजिज फंड का प्रावधान किया गया हैं । इसी तरह स्वंत्रतता सेनानियों को वर्तमान में देय सम्मान पेंशन राशि 50 हजार रुपए को बढ़ाकर अब 60 हजार रुपए प्रतिमाह का प्रावधान किया गया हैं।

इसी तरह सुशासन के लिए प्रशासन की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों में इस वित्त वर्ष में 250 वाहन , ऊर्जा विभाग में 13 नये विद्युत कार्यालय, छह नये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय, खान विभाग केतीन नवीन कार्यालय, सात नवीन तहसील कार्यालय, 20 नवीन नगर पालिकाये, पुष्कर अजमेर, लालसोट-दौसा एवं शाहपुरा-जयपुर में नगर परिषद एवं पाली एवं भीलवाड़ा में नगर निगम का प्रावधान किया गया हैं । पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)- 5 महत्वपूर्ण लिंक एवं चंबल बेसिन के कार्य चरणबद्ध रुप से , सौ एनिकटो का निर्माण एवं मरमम्त एवं जीणोद्धार, सौ बाधों एवं नहरों का जीणोद्धार कार्य का प्रावधान किया गया हैं।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पन्द्रह हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान

जयपुर। राजस्थान सरकार के बुधवार को विधानसभा में पेश किए बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सम्पूर्ण प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू करने , प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी , 125 करोड़ रुपये व्यय , मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आगामी तीन वर्षो में 15 हजार करोड़ रुपये के कार्य करने का प्रावधान किया गया हैं। बजट में सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय ,जयपुर के आयुष्मान टावर हेतु लगभग 200 करोड़ रुपये व्यय , अजमेर में आयुर्वेद , योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं एक हजार 500 चिकित्सकों तथा चार हजार नर्सिंग कर्मियों के नये पद सृजित किए जायेंगे। इसी तरह सड़क सुरक्षा क्षेत्र में आरयूएचएस जयपुर , कोलाना (बांदीकुई) दौसा , साण्डेराव , देसूरी-पाली एवं प्रतापगढ़ सहित छह नये ट्रोमा सेंटर , 25 अतिरिक्त उन्नत जीवन सुरक्षा एम्बुलेंस , प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर सड़क सुरक्षा टॉस्क फोर्स का प्रावधान किया गया है। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना में 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी सकी आधारभूत संरचनाओं के लिए दो सौ करोड़ रुपये का प्रावधान , शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडरों के साथ अन्य जरुरतमंद एवं असहाय परिवारों के लिए , प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को 25 हजार रुपये का अनुदान , ईडब्ल्यूएस हेतु रियायती ब्याज दर पर रिण के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान , प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच-पांच नवीन आंगनबाडी केन्द्र , लखपति दीदी योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का पांच लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने तथा दो हजार दिव्यांगजन को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया है।

जयपुर पुलिस आयुक्तालय में पृथक से सुरक्षा पुलिस बल , पद्मिनी , कालीबाई एवं अमृतादेवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना , पुलिस के लिए 750 मोटरसाइकिल एवं पांच सौ हल्के वाहन एवं विभिन्न नये न्यायालयों की स्थापना , प्रत्येक जिले में एक महिला थाना एवं 10 नये पुलिस थाने खोलने का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह कार्मिक कल्याण पेंशनर्स को देय आउट डोर चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा का 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष , ग्रेच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 120 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।

इसी तरह स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की आयु सीमा तथा अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष किया गया है। उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार प्रारंभ किया गया एवं अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जायेगी।

दीया कुमारी ने तोड़ा अशोक गहलोत का रिकॉर्ड, 2 घंटे 50 मिनट का दिया बजट भाषण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट पेश किया। दीया कुमारी ने विधानसभा में 2 घंटे 50 मिनट लंबा बजट भाषण दिया। इससे पहले विधानसभा में अशोक गहलोत ने 2 घंटे 18 मिनिट तक बजट भाषण दिया था। घंटे 50 मिनट लंबा बजट भाषण देकर दीया कुमारी ने अशेक गहलोत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वित्त मंत्री के रूप में यह दीया कुमारी का पहला बजट भाषण था। बजट भाषण में दीया कुमारी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए की कई बड़ी घोषणाएं सरकार आने वाले 5 साल में 4 लाख से ज्यादा नई नौकरी देगी। 10 लाख युवाओं को निजी सेक्टर में रोजगार मुहैया करवाने की घोषणा की है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में अब तक का सबसे अच्छा बजट : खींवसर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दीया कुमारी पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा। अपने पहले बजट भाषण में वित्त मंत्री ने युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। बजट के बाद मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बजट को बेहतरीन बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का परिवर्तित बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत-2047 की परिकल्पना को मूर्तरूप देने की दिशा में बड़ा कदम है। विकसित भारत को लेकर बजट में दिए गए 10 संकल्प विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए 8.26 प्रतिशत बजट प्रावधान रखना यह इंगित करता है कि राज्य सरकार चिकित्सा क्षेत्र को लेकर बेहद संवेदनशील है। स्वास्थ्य के लिए अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान रखे जाने पर मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, उगीग, कृषि, आधारभूत वाचे, पर्यटन सहित सभी क्षेत्री के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो न केवल प्रदेश के विकास को गति देगी, बल्कि विकसित राजस्थान के हमारे संकल्प को भी साकार करेगी। विरासत और विकास के बेहतर समन्वय की सोच के साथ लाया गया यह बजट जन उम्मीदों को पूरा करने वाला है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 83 हजार किलोमीटर सडक विकास, 4 लाख पदों पर भर्तिया करने, 6 बृहद पेयजल परियोजनाएं शुरु करने, विभिन्न क्षेत्रों में कामकाज को सुगम बनाने के लिए नई नीतियां लाने जैसी घोषणाएं की हैं। ये घोषणाएं प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बजट में स्याराध्य के क्षेत्र के लिए 27 हजार 660 करोड़ रुपए का प्राधान रखते हुए कई जनोन्मुखी घोषणाएं की गई है. जिनसे आमजन को गांव ढाणी तक सुगमतापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में शिशुओं के उपचार हेतु पैकेज जोड़ने, अस्पतालों के एम्पेनलमेंट के नियमों को सरल करने, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए मा वाउचर योजना लागू करने, चिकित्सकों के 1500 प 4 हजार नर्सिंगकर्मियों के पदों का सूजन, मा हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने, हर विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान मॉडल सीएवसी स्थापित कर सुविधाओं में बढ़ोतरी एवं मोर्चरी निर्माण करने सहित कई अहम घोषणाएं बजट में की गई है, जिनसे स्वास्थ्य सेवाओं का उत्थान होगा और आयुष्मान राजस्थान का संकल्प फलीभूत होगा।

सिर्फ खानापूर्ति हुई है, भजनलाल सरकार के बजट पर सचिन पायलट बोले

जयपुर। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भजनलाल सरकार के पूर्ण बजट पर प्रतिक्रिया दी है। सचिन पायलट ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा- बजट से हमे उम्मीद थी कि प्रदेश में लगातार जो मंहगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है उसपर कुछ ठोस कदम उठाएंगे लेकिन बजट भाषण को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है की सिर्फ खानापूर्ति हुई है कुछ ठोस कदम नही उठाये। जिन मूलभूत सुविधाएं की जनता को जरूरत थी।

भजनलाल सरकार का पूर्ण बजट 2024-25 नीरस और दिशाहीन : अशोक गहलोत

जयपुर । पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार के पूर्ण बजट 2024-25 को नीरस और दिशाहीन बताया है । गहलोत ने एक्स पर कहा कि आज राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए बजट का शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि इस बजट से ना जनता को राहत मिली है और ना ही कोई विकास का रोडमैप बन रहा है।गहलोत ने कहा कि जनता को उम्मीद थी कि मोदी की गारंटी के मुताबिक पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम की जाएंगी परन्तु ऐसा नहीं किया गया। बल्कि हमारी सरकार की महंगाई से राहत देने वाली योजनाओं जैसे 100 यूनिट फ्री बिजली, अन्नपूर्णा राशन किट, इन्दिरा रसोई, फ्री कृषि बिजली आदि के लिए कोई बजट आंवटन नहीं किया है यानी आने वाले दिनों में जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। बजट के दिन ही रोडवेज एसी बसों का किराया 10 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाकर सरकार ने अपना उद्देश्य जाहिर कर दिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार ने बजट में नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की उम्मठ बनाने की घोषणा कर वाहवाही लेने का प्रयास किया है। हमारी सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 10 करोड़ रुपये सड़कों के लिए देती थी जिसे इस सरकार ने 5 करोड़ रुपये कर दिया है। यह दिखाता है कि ये सरकार काम में नहीं सिर्फ पैकेजिंग में भरोसा करती है।

राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटों में बादलों की गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई जबकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमन्द जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई है। जयपुर मौसम केन्द्र के अनुसार, इस दौरान पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश बांसवाड़ा के बागीडोरा में 80 मिलीमीटर, ओबारी में 79 मिमी, डूंगरपुर के गणेशपुर में 66 मिमी, राजसमंद के देलवाड़ा में 72 मिमी और पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर के गदरा रोड में 50 मिमी बारिश हुई।

मौसम केन्द्र के अनुसार, पिछले 24 घंटों में जैसलमेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41.0 डिग्री सेल्सियस तथा बीकानेर में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 31.5 डिग्री दर्ज किया गया। केन्द्र के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बुधवार को एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है तथा मानसून जैसलमेर, कोटा से होकर गुजर रहा है।

उन्होंने बताया कि इसके प्रभाव से आगामी 24 घंटे में जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। आज 10 जुलाई को उदयपुर संभाग में और 11 जुलाई को भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। प्रवक्ता ने बताया कि बृहस्पतिवार से मानसून ट्रफ लाइन के हिमालय की ओर जाने से बारिश में कमी होने की संभावना है। 11-15 जुलाई को छुटपुट स्थानों पर बादलों की गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

उन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में 11-12 जुलाई को अपेक्षाकृत तेज सतही हवाएं चलने व केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 13 से 15 जुलाई के दौरान अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।

चर्चा में बने रहने के लिए डोटासरा देते रहते हैं नौटंकीपूर्ण बयान : चौधरी

जयपुर। राजस्थान के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बजट को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डोटासरा सत्ता जाने के बाद मानसिक संतुलन खो चुके हैं और चर्चा में बने रहने के लिए नौटंकीपूर्ण और हास्यास्पद बयान देते रहते हैं। चौधरी ने मंगलवार को यहां जारी बयान में कहा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भजनलाल सरकार महज छह महीने में अपने ऐतिहासिक निर्णयों के साथ अपने संकल्प पत्र की ज्यादातर घोषणाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक जैसी घटनाओं पर ढिलाई बरतने वाले और मौन रहने वाले डोटासरा सत्ता जाने के बाद भाजपा की जनहितैषी सरकार के कामों में कमी निकाल रहे हैं।

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ें और केवल अवसर ही नहीं बढ़ें बल्कि उनमें पारदर्शिता हो, कोई पेपर माफिया हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके इसके लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन हुआ और अब पेपर लीक में शामिल रहे लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं।

चौधरी ने कहा कि डोटासरा यह समझ लें कि अब पर्चियों पर लिख लिखकर अपने रिश्तेदारों को अफसर बनाने वाले दिन गये। राज्य में जनवरी से लेकर जुलाई तक छोटी बड़ी 90 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, और सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई किसी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस और टैंकर की टक्कर में 18 लोगों की मौत, 19 घायल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

उन्नाव (उप्र)/भाषा। उन्नाव जिले में बुधवार को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस और टैंकर की टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मृतकों में एक ही परिवार के छह सदस्य शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि घटना तड़के करीब पांच बजे बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में जोजीकोट गांव के पास हुई, बस में 60 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार के मोतिहारी से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस की रफ्तार तेज थी और उसने दूध के टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी। जिलाधिकारी ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। राठी ने बताया कि हादसे में मामूली रूप से घायल हुए 20 अन्य यात्रियों को दूसरी बस से दिल्ली भेजा गया है। अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) एसबी शिरोडकर ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 14 पुरुष, तीन महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। उन्होंने बताया कि हादसे में 19 लोग घायल हो गये हैं। बांगरमऊ के क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि मरने वाले 18 लोगों में से 10 की पहचान हो चुकी हैं। मरने वालों में मेरठ के एक ही परिवार के अशफाक (45), रूबी (40), गुलनाज (12), सुहैल (4), सोनू (32) तथा सोनी (28) शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना में बिहार निवासी बस चालक अखलाक (49) और दूध कैंटर चालक रायबरेली निवासी सुनील कुमार (35) की भी मौत हो गयी है। दो अन्य मृतकों की पहचान बिहार के दीपक कुमार (27) और शिव दयाल (28) के रूप में हुई है।

उन्नाव के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने बताया कि बिहार से दिल्ली जा रही इस निजी बस में करीब 60 यात्री सवार थे, जो अलग अलग स्थानों से सवार हुए थे। बांगरमऊ के क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और टैंकर दोनों पलट गये। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची बांगरमऊ कोतवाली और उप्र एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की टीम ने बस में फंसे लोगों को बाहर निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय सर्वेक्षण किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पीलीभीत/लखीमपुर खीरी (उप्र)/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया और कहा कि संकट के इस समय में सरकार सभी बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पीलीभीत की पूरनपुर, सदर और बीसलपुर तहसील के बाढ़ प्रभावित गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति की जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने पीलीभीत के चंदिया हजारा और अध्यापुर जगतपुर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा से प्रभावित बच्चों, महिलाओं और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। आदित्यनाथ ने आपदा से प्रभावित लोगों से कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 133 गांव जुलाई माह के पहले सप्ताह में ही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में हैं, हजारों हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है और बाढ़ से बचाव के लिये जन प्रतिनिधि व स्थानीय प्रशासन पूरी तरह जुटे हुए हैं।

आदित्यानाथ ने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई थी, इसी वजह से जुलाई के पहले हफ्ते में ही प्रभावित इलाकों के लोगों को बाढ़ से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग नदी और तटबंध के बीच में रहते हैं वे हर बार बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, अगर वे सहमति देंगे तो सरकार उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाने की व्यवस्था करेगी। आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित कुछ लोगों को खुद राहत सामग्री वितरित की, इसके बाद वह बाढ़ राहत शिविर पहुंचे और वहां ठहरे लोगों का हालचाल जाना। उन्होंने जिले के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ राहत कार्यों में तेजी लाने और समय रहते राहत सामग्री बांटने एवं सहायता राशि देने के निर्देश दिये। उन्होंने खराब हुईं फसलों का तत्काल सर्वे कराकर सहायता राशि उपलब्ध कराने के आदेश दिये।

इसके बाद आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित पीलीभीत के इलाकों का दौरा करने के बाद लखीमपुर खीरी पहुंचे। वहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। बाद में उन्होंने सोरिया ग्राम सभा के मजरा महादेव में नाव पर बैठकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी के शारदा नगर पहुंचकर शारदा नदी पर बने बैराज से नदी के जलस्तर को देखा, साथ ही अधिकारियों से जानकारी हासिल की। उन्होंने शारदा नगर के बाढ़ राहत शिविर जाकर आपदा प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी। आदित्यनाथ ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश के 12 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां पर युद्धस्तर पर राहत कार्य जारी हैं।

पहले सरकारी भर्ती प्रक्रिया में चाचा-भतीजे की जोड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी: आदित्यनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले सरकारी भर्ती प्रक्रिया में चाचा-भतीजे की जोड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी।

आदित्यनाथ बिना नाम लिए अकसर समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के लिए चाचा-भतीजा शब्द इस्तेमाल करते हैं। 2017 से पहले राज्य में सपा की सरकार थी और अखिलेश मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि 2022 में राजस्व विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, आयोग ने चयन प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संचालित किया। हालांकि, हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर अच्छी पहल में बाधा डालने की कोशिश करते हैं।

यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने लोक भवन में आयोजित मिशन रोजगार कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) द्वारा निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चयनित 7,720 लेखपाल को नियुक्ति पत्र बांटे। आदित्यनाथ ने कहा, 2017 से पहले (सपा शासनकाल में), लेखपाल के आधे पद दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के कारण खाली थे। प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही, 'चाचा-भतीजे' की जोड़ी भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर सभी जिलों को परिवार के सदस्यों के बीच बांट देती थी। उन्होंने कहा, यह वही उत्तर प्रदेश है जिसके युवा अगर कहीं बाहर जाते थे तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता था। कुछ जिलों की छवि इतनी खराब थी कि लोग उन्हें होटल और धर्मशालाओं में भी जगह नहीं देते थे, नौकरी तो दूर की बात है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके शासनकाल में यह चयन प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव या सिफारिश के पूरी निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ की गई। उन्होंने कहा कि भर्ती किए गए उम्मीदवारों का यह कर्तव्य है कि वे सिफारिशों पर भरोसा किए बिना लगन से काम करें और राज्य में व्यापार करने में आसानी व गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करें।

गौशाला में बाजरा खाने से छह गायों की मौत, दो अधिकारी निलंबित

संभल (उप्र)/भाषा। संभल जिले में बुधवार को एक सरकारी गौशाला में कथित रूप से दूषित बाजरा खाने से छह गायों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने लापरवाही बरतने के आरोप में पशुधन अधिकारी समेत दो अफसरों को निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसियां ने बताया कि संभल थाना क्षेत्र में स्थित शरीफपुर गांव में एक सरकारी गौशाला में बाजरा खाने के बाद कई गायों की तबीयत अचानक खराब हो गई और देखते ही देखते उनमें से छह गायों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि छह अन्य बीमार गायों का इलाज किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी सौरभ सिंह और पशु धन विभाग के अधिकारी शिवम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा खंड विकास अधिकारी समेत चार अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि मृत गायों के नमूने जांच के लिए बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) भेजे गए हैं ,जांच के बाद उनकी मौत का असल कारण पता लग सकेगा।

ओडिशा का विश्वविद्यालय औषधीय पौधों के लिए उद्यान स्थापित करेगा

बेरहामपुर (ओडिशा)/भाषा। ओडिशा के बेरहामपुर विश्वविद्यालय ने विलुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण और औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने परिसर में दो उद्यान स्थापित करने का निर्णय लिया है। कुलपति गीतांजलि दास ने कहा इन विशिष्ट उद्यानों का दोहरा लक्ष्य विलुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों का संरक्षण और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में शैक्षिक एवं अनुसंधान उद्देश्यों के लिए औषधीय पौधे तैयार करना है। विलुप्तप्राय प्रजातियों के लिए उद्यान में 73 विभिन्न प्रजातियों के 200 पौधे लगाए जाएंगे, जबकि राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त 93 औषधीय प्रजातियों के 300 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री का मणिपुर की यात्रा करना या नहीं करना कोई मुद्दा ही नहीं : एन. बीरेन सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंफाल/भाषा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य का दौरा किया जाना या नहीं किया जाना, कोई मुद्दा ही नहीं है क्योंकि उनकी सरकार चौबीसों घंटे उनके संपर्क में है। सिंह का यह बयान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के दो दिन बाद आया है। गांधी ने सोमवार को मणिपुर का दौरा किया था और प्रधानमंत्री मोदी से जातीय संघर्ष से प्रभावित राज्य में आकर लोगों को सांत्वना देने का अनुरोध किया था।

मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक से इतर संवाददाताओं से कहा, ''यह कोई सवाल ही नहीं है कि प्रधानमंत्री राज्य का दौरा करते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री का आना स्थिति पर निर्भर करता है।'' सिंह ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ''स्थिति'' से उनका क्या अभिप्राय है। उन्होंने कहा, ''हम चौबीसों घंटे उनके संपर्क में हैं और उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। सभी राहत कार्य, सुरक्षा उपाय, खाद्य और चिकित्सा प्रावधान प्रधानमंत्री की सलाह और सहमति के बाद ही किए जा रहे हैं।''

पूर्वोत्तर राज्य में मेइती और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में पिछले वर्ष मई से अब तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। सिंह ने कहा, ''दोनों समुदायों के बीच सुलह के प्रयास जारी हैं। हमें मुद्दों को सुलझाना होगा।'' उन्होंने कहा कि भाजपा की बैठक में, राज्य में हाल में आई बाढ़ पर भी चर्चा हुई।

मणिपुर: कुकी बहुल इलाकों में 12 घंटे के ''पूर्ण बंद'' के कारण जनजीवन प्रभावित

इंफाल/चुराचांदपुर/भाषा। मणिपुर में कुकी समुदाय के पांच लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में एक प्रमुख कुकी संगठन द्वारा आहूत 12 घंटे के ''पूर्ण बंद'' के कारण बुधवार को कम से कम चार जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ। 'कुकी इंपी' ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा था कि वह बुधवार को सुबह छह बजे से शाम छह बजे के बीच बंद लागू करेगा।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस बंद के कारण चुराचांदपुर, कांगपोकपी, फेरजौल और तेंगनौपाल जिलों में बाजार, शैक्षणिक संस्थान और बैंक बंद रहे। उन्होंने बताया कि सरकारी कार्यालयों में भी उपस्थिति कम रही।

सूत्रों ने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए चुराचांदपुर और कांगपोकपी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है कि कोई अप्रिय घटना नहीं हो। चुराचांदपुर और तेंगनौपाल में कुकी समुदाय के पांच लोगों की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए लोगों ने कई स्थानों पर प्रदर्शन किए और नारे लगाए।

'ओडिया अस्मिता' को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का कोष बनाएगी ओडिशा सरकार

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा सरकार के मंत्रिमंडल ने बुधवार को 'ओडिया अस्मिता' के पुनरोत्थान और राज्य की कला, संस्कृति एवं विरासत को बढ़ावा देने के वास्ते विभिन्न पहल के लिये 200 करोड़ रुपये का कोष बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि इस निधि का उपयोग ओडिशा अस्मिता भवन, ओडिया अनुवाद अकादमी, विश्व स्तरीय ताड़पत्र पांडुलिपि संग्रहालय की स्थापना, पाइका विद्रोह स्मारक के विकास और जिला स्तर पर ई-पुस्तकालय के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में ओडिया पीठ की स्थापना, ओडिसी संगीत और नृत्य में प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता और सांस्कृतिक मंडली प्रबंधन प्रणाली का विकास भी पहल का हिस्सा होगा। तीन घंटे तक चली राज्य कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता माझी ने की। बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, कैबिनेट ने ओडिया अस्मिता के पुनरोत्थान और ओडिया कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का कोष बनाने का फैसला किया है। राज्य में 12 जून को सत्ता संभालने के बाद से भाजपा सरकार की यह दूसरी कैबिनेट बैठक थी। मंत्रिपरिषद ने राज्य में अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च-कुशल श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी को संशोधित करने को भी मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि अकुशल और उच्च-कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 98 रुपये बढ़ा दी गई है, जबकि अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी में 108 रुपये प्रति दिन की वृद्धि की गई है।

भाजपा की शिक्षा विरोधी नीयत के कारण मेधावी युवाओं का भविष्य अधर में: राहुल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के छात्रों के प्लेसमेंट और वार्षिक पैकेज में कथित तौर पर गिरावट को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की शिक्षा विरोधी नीयत के कारण मेधावी युवाओं का भविष्य अधर में है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष अपनी पूरी शक्ति से युवाओं की आवाज निरंतर उठाता रहेगा और इस अन्याय पर सरकार को जवाबदेह बनाकर रहेगा।

राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक खबर साझा करते हुए कहा, ''आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव अब देश के सबसे प्रतिष्ठित आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी झेल रहे हैं। आईआईटी में प्लेसमेंट और वार्षिक पैकेज में गिरावट, बेरोज़गारी का चरम झेल रहे युवाओं की स्थिति पर और गहरा आघात कर रहे हैं। 2022 में 19 प्रतिशत छात्रों को कैम्पस प्लेसमेंट नहीं मिल सका और इस वर्ष वही दर बढ़कर दोगुनी, यानी 38 प्रतिशत हो गयी।'' उनका कहना है कि जब देश के सबसे प्रसिद्ध एवं सम्मानित शिक्षा संस्थानों का यह हाल है तो बाकी संस्थानों की क्या दुर्गति होगी? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया, ''आज युवा बेरोज़गारी से पूरी तरह टूट चुका है - पेशेवर शिक्षा पाने में माता-पिता लाखों खर्च कर रहे हैं, विद्यार्थी ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज ले कर पढ़ने पर मजबूर हैं। फिर नौकरी न मिलना, या साधारण आमदनी उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट ही पैदा कर रही है।'' उन्होंने आरोप लगाया, ''यह भाजपा की शिक्षा विरोधी नीयत का ही नतीजा है जो इस देश के मेधावी युवाओं का भविष्य अधर में है।'' राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्या मोदी सरकार के पास भारत के मेहनती युवाओं को इस संकट से मुक्ति दिलाने की कोई योजना भी है? उन्होंने कहा, ''विपक्ष पूरी शक्ति से युवाओं की आवाज निरंतर उठाता रहेगा, इस अन्याय पर सरकार को जवाबदेह बनाकर रहेगा।''

गंभीर के बिना केकेआर के लिए बड़ी चुनौती होगी : चंद्रकांत पंडित

कोलकाता/भाषा। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और टीम इंडिया दोनों बदलाव के दौर से गुजरेंगी क्योंकि गौतम गंभीर ने केकेआर फ्रेंचाइजी छोड़कर राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच का पदभार संभाल लिया है। केकेआर को अपनी अगुआई में 2012 और 2014 में दो खिताब दिलाने वाले गंभीर ने बतौर मेंटोर 2024 में फ्रेंचाइजी को खिताब दिलाया। इस दौरान केकेआर 2021 के फाइनल में भी पहुंची। केकेआर के सह मालिक शाहरुख खान ने गंभीर के मेंटोर बनाये जाने पर उनसे कहा था, ''यह आपकी फ्रेंचाइजी है, इसे बना दो या बिगाड़ दो।''

इस बीच दोनों के बीच क्रिकेट से संबंधित कोई बात नहीं हुई और गंभीर टीम को आईपीएल 2024 विजेता बनाने में सफल रहे। कोचिंग के अपने अनुभव की वजह से 'गुरु गंभीर' भारतीय टीम के मुख्य कोच के पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे और मंगलवार को इस पद पर विराजमान हुए। केकेआर के मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित की भी केकेआर को विजेता बनाने में अहम भूमिका रही और उनके फ्रेंचाइजी के साथ अनुबंध का एक साल और बचा है। अब केकेआर गंभीर के बिना होगी जिसे पंडित ने बड़ी चुनौती करार दिया। पंडित ने पीटीआई से कहा, ''हम आईपीएल में बतौर गत चैम्पियन प्रवेश करेंगे जो बड़ी चीज होगी। हर साल जब जिस भी टूर्नामेंट में खेलते हो, कोचों, सहयोगी स्टाफ और खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती होती है। पंडित ने कहा, हर किसी ने योगदान दिया। इसी तरह गौतम कप्तान और मेंटोर के तौर पर अपार अनुभव के साथ आये जिससे भी टीम को मदद मिली। निश्चित रूप से कप्तानी और खिलाड़ियों के मेंटोर के तौर पर टीम को काफी मदद मिली।

बंगाल पुलिस ने युवती पर हमला मामले में तीसरी गिरफ्तारी की

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक क्लब में सामूहिक रूप से युवती पर हमला करने की घटना के सिलसिले में पुलिस ने स्थानीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता जयंत सिंह के एक और करीबी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। बैरकपुर पुलिस आयुक्त सीपी आलोक राजोरिया ने बताया कि गिरफ्तारी मंगलवार देर रात हुई। उन्होंने कहा कि घटना के वीडियो फुटेज के आधार पर आठ लोगों की पहचान की गई है।

रजोरिया ने कहा कि पुराना वीडियो होने के कारण भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा, ''हमने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराएं भी जोड़ी हैं।'' एक अन्य मामले में 2023 में गिरफ्तारी के बाद भविष्य में कोई अवैध गतिविधियां नहीं करने के वादे के बाद जमानत पर छोड़े गए सिंह के खिलाफ वादा खिलाफी के अतिरिक्त आरोप लगाए गए हैं।

यह घटना मंगलवार की सुबह तब सामने आई जब कुछ लोगों के एक युवती के पैर और हाथ पकड़कर डंडों से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर आया। पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू की और दो लोगों को गिरफ्तार किया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह वीडियो कम से कम दो वर्ष पुराना है। हालांकि पीटीआई भाषा वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

नीतीश ने निजी कंपनी के अधिकारी को पैर छूने की पेशकश कर शर्मिंदा किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को यहां रोडवेज परियोजना का जिम्मा संभाल रही एक निजी कंपनी के एक प्रतिनिधि को पैर छूने की पेशकश कर शर्मिंदा करने की कोशिश की। पटना में जेपी गंगा पथ के दूसरे चरण का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री जैसे ही वहां से चलने के लिए उठे तो सामने खड़े निर्माण एजेंसी के इंजीनियर से कहा कि तेजी से काम को पूरा करें। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी काम पूरा होना चाहिए.. कहिए तो आपके पैर भी छू लेंगे।

कुमार इंजीनियर का पैर छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, वहां मौजूद पथ निर्माण विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत ने हाथ जोड़कर उनका रास्ता रोक लिया और ऐसा नहीं करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तथा स्थानीय सांसद रवि शंकर प्रसाद भी मौजूद थे। एक सप्ताह पहले भी मुख्यमंत्री ने आईएएस अधिकारी के पैर छूने की पेशकश करते हुए व्यापक सर्वेक्षण करके भूमि विवादों को जल्दी से जल्दी निपटाने का आग्रह किया था।

बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक वीडियो फुटेज साझा करते हुए लिखा, पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई ही मुख्यमंत्री होगा जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर वरीय अधिकारियों और यहाँ तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने बात-बात पर हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता हो? उन्होंने लिखा, बिहार में बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, पलायन एवं प्रशासनिक अराजकता का मुख्य कारण यह है कि एक कर्मचारी तक (अधिकारी तो छोड़िए) मुख्यमंत्री की नहीं सुनता? क्यों नहीं सुनता और क्यों नहीं आदेशों का पालन करता, यह विचारनीय विषय है?

न्यायालय ने बंगाल के वाद को विचारणीय बताते हुए कहा केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है सीबीआई

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के एक वाद की विचारणीयता पर केंद्र की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में सहमति वापस लिए जाने के बाद भी सीबीआई के तफ्तीश करने के विरोध में राज्य द्वारा दायर मुकदमे की विचारणीयता पर केंद्र की आपत्ति को खारिज कर दिया।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को 16 नवंबर, 2018 को राज्य में मामलों की जांच करने या छापे मारने के लिए दी गई अनुमति को वापस ले लिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 के एक प्रावधान के अनुसार भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत अपराधों के लिए मामलों को लेकर नियंत्रण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है। न्यायालय ने डीएसपीई कानून के अनेक प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा, ''हम यह भी पाते हैं कि स्थापना, शक्तियों का प्रयोग, अधिकार क्षेत्र का विस्तार, डीएसपीई का नियंत्रण, सबकुछ भारत सरकार के पास है।''

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने व्यवस्था दी थी कि मुकदमा विचारणीय है। पीठ ने कहा, ''हमारे विचार से सीबीआई एक शाखा या अंग है जिसकी स्थापना डीएसपीई कानून द्वारा लागू वैधानिक योजना के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा की गई और वह भारत सरकार के अधीन है।'' पीठ ने अपने 74 पन्नों के फैसले में कहा, ''इतना ही नहीं, जिन अपराधों को केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करती है, उनमें ही डीएसपीई द्वारा जांच की जा सकती है।'' इसने कहा कि डीएसपीई अधिनियम की धारा 4 के तहत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों को छोड़कर, जिसमें अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास होगा, अन्य सभी मामलों में डीएसपीई का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होगा।

सुविचार

किसी ने यूँ ही पूछ लिया हमसे की दर्द की कीमत क्या है, हमने हँसते हुए कहा पता नहीं कुछ अपने मुफ्त में दे जाते है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

'वरदान' का सदुपयोग करें

देश में घटते भूजल संबंधी आंकड़े भविष्य में इस समस्या के और गंभीर होने के संकेत दे रहे हैं। भूजल के अतिदोहन से कई इलाकों में तो हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। ऐसे में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर के एक नए अध्ययन में किया गया यह दावा कि 'उत्तर भारत में साल 2002 से लेकर 2021 तक लगभग 450 घन किलोमीटर भूजल घट गया और निकट भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी मात्रा में और भी गिरावट आएगी', बताता है कि भूजल स्तर बढ़ाने के लिए ठोस उपाय करने की जरूरत है। देश में गर्मियों का मौसम आते ही कई इलाकों में पेयजल संकट गहरा जाता है। इस साल राष्ट्रीय राजधानी से लेकर बेंगलूरु और चेन्नई जैसे शहरों में भी लोग खासे परेशान रहे। जनता इस समस्या से किसी तरह निजात पाने की कोशिश करती है कि मानसून आ जाता है। कई राज्यों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। सामान्य बारिश की स्थिति में भी नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे बारिश के पानी से लबालब रहते हैं। एक तरफ पेयजल के लिए ऐसा हाहाकार, दूसरी तरफ बारिश के मौसम में सर्वत्र पानी ही पानी! ये दोनों तस्वीरें बताती हैं कि पानी के इस संकट के लिए कहीं-न-कहीं हम जिम्मेदार हैं। जब कुदरत हमारे देश पर इतनी मेहरबान है तो उसके वरदान का सदुपयोग करने में देरी क्यों की गई? दशकों तक अनदेखी और भूजल के अतिदोहन का नतीजा यह निकला कि कई इलाकों में ऐसे कुएं भी सूखे पड़े हैं, जिनके पानी से कई एकड़ में फसलें तैयार होती थीं।

हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) के शोधार्थियों के दल के इस निष्कर्ष को नहीं भूलना चाहिए कि 'मानसून के दौरान कम बारिश होने और सर्दियों के दौरान तापमान बढ़ने के कारण सिंचाई के लिए पानी की मांग बढ़ेगी और इसके कारण भूजल पुनर्भरण में कमी आएगी, जिससे उत्तर भारत में पहले से ही कम हो रहे भूजल संसाधन पर और अधिक दबाव पड़ेगा।' स्पष्ट है कि सिंचाई के लिए कम पानी होगा तो नई पीढ़ी के किसान खेती से दूर होंगे। उन्हें आमदनी के दूसरे स्रोत तलाशने होंगे। राजस्थान के कई इलाकों में ऐसा हो रहा है। वहां कई खेत हैं, जो आज वीरान पड़े हैं, क्योंकि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। कभी उन खेतों में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि की फसलें लहलहाती थीं। अब वहां बाजरा, ग्वार, मूंग की ही खेती होती है, वह भी मानसून के भरोसे। अगर समय पर मानसून आ गया तो बुआई अच्छी हो जाएगी, लेकिन यह भरपूर उत्पादन होने की गारंटी नहीं है। फसल तैयार होते समय जरूरत के मुताबिक बारिश न हुई तो सबकुछ चौपट हो सकता है। भूजल के घटते स्तर का समाधान भूजल पुनर्भरण में है। इसके लिए सरकारों को गंभीरता से काम करना होगा। हर मकान, आवासीय/व्यावसायिक इमारत, सार्वजनिक महत्त्व के भवनों की छतों से वर्षाजल को इकट्ठा कर वैज्ञानिक विधियों से भूजल पुनर्भरण करें। हर साल कितना ही वर्षाजल नालियों में बह जाता है, जो न तो पीने के काम आता है और न ही घरेलू कामों का उसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे कई बार हादसे भी होते हैं। भूजल पुनर्भरण की प्रणाली स्थापित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। प्राय: माना जाता है कि भूजल पुनर्भरण तो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है! हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस तेजी से भूजल घट रहा है, उसका असर सभी पर होगा। आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। भविष्य में हालात और ज्यादा मुश्किल न हों, इसके लिए तैयारी अभी से करनी होगी।

ट्वीटर टॉक

माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं माननीय उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री श्रीमती दीया कुमारी ने राजस्थान को विकसित भारत निर्माण के लक्ष्य में आगे रखने वाली आर्थिकी तैयार की है। संस्कृति और पर्यटन को विशेष प्राथमिकता में रखा जाना महत्वपूर्ण है।

-गजेन्द्र सिंह शेखावत

अमृत काल खंड में विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना को साकार करने हेतु आगामी पाँच वर्षों की कार्य योजना तैयार की गई है। सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार ने भविष्य हेतु 10 संकल्प लिए हैं।

-दीया कुमारी

माननीय रक्षा मंत्री और वरिष्ठ राजनेता श्री राजनाथ सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य शक्ति के सुदृढ़ीकरण में आपका वृहद अनुभव तथा कुशल मार्गदर्शन सभी के लिए प्रेरक है। ईश्वर से आपके दीर्घ, सुयशपूर्ण जीवन की कामना करता हूँ।

-ओम बिरला

प्रेरक प्रसंग

कल्याणकारी असत्य

एक बार एक राजा ने एक कैदी को किसी संगीन अपराध पर मृत्यु की सजा सुनायी। कैदी ने सोचा कि मरना ही है, तब राजा से क्या डरना। अत: उसने राजा को अनेक गालियां दे डालीं। राजा कैदी की भाषा कुछ कम समझता था और कुछ वह जानबूझकर अनजान बन गया। उसने अपने मंत्री से पूछा कि कैदी क्या कह रहा है? मंत्री- 'महाराज, ये कैदी कह रहा है कि जो क्षमा करना जानता है, वह ईश्वर को प्रिय होता है।' राजा-'अरे! ऐसी बात है तो इसको ससम्मान छोड़ दिया जाए।' दूसरा मंत्री-'राजन! मंत्री जी आपसे झूठ बोल रहे हैं। कैदी तो आपको गालियां दे रहा है।' राजा-'मंत्री जी, आपकी सत्यता से मुझे आपके साथी मंत्री का झूठ अधिक अच्छा लगा क्योंकि इस झूठ में एक जीवन को बचाने का आग्रह है। अतः यह झूठ होते हुए भी झूठ नहीं है, जबकि तुम्हारे सत्य में द्वेष का विष है। अतः यह सत्य होकर भी अच्छा नहीं है।' राजा ने यह कहकर कैदी को मुक्त कर दिया।

सामयिक

रूस भारत के सहयोग के लिये तत्पर रहता है, इसबार भी यह खबर भी सुकून देने वाली है कि रूस ने भारत के आग्रह पर न केवल रूसी सेना के सपोर्ट स्टाफ के रूप में भारतीयों की नियुक्ति रोकना स्वीकार कर लिया है बल्कि नियुक्त किए जा चुके युवाओं को स्वदेश भेजने पर भी मान गया है। इस ष्टि से प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा सफल कूटनीति के एक उत्तम उदाहरण के रूप में याद रखी जाएगी। भारतीय हितों की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व मानवता की बात करना इसी रणनीति का हिस्सा था।

भारत-रूस मित्रता को जीवंतता देने का सार्थक प्रयास

ललित गर्ग

भारत-रूस की मैत्री को नये आयाम देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति पूतिन ने न केवल मैत्री के धागों एवं द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती दी है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को नये शिखर देने का प्रयास किया है। उनकी यह यात्रा दोनों देशों के लिये एक नए सोच के साथ नये सफर का आगाज है। एक ऐसे समय में, जबकि यूक्रेन-रूस युद्ध को पश्चिमी देशों के विरोध के कारण रूस दुनिया में अलग-थलग है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में पहले विदेश यात्रा के लिये रूस का चयन करके जता दिया है कि भारत-रूस की मैत्री अक्षुण्ण है और किसी भी तरह के दुनिया के दबाव में यह दोस्ती कमजोर नहीं पड़ने वाली है। भारत ने जहां मैत्री को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में उल्लेखनीय उपक्रम किये हैं, वहीं अपने मित्र देश को युद्ध के खिलाफ और शांति के पक्ष में अपना स्पष्ट रुख भी जताया है। मोदी की इस यात्रा की एक बड़ी निष्पत्ति यह है कि रूस में अब दो नये वाणिज्यिक दूतावास खुलने जा रहे हैं, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियां तेजी से एवं ज्यादा बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस रूस यात्रा को लेकर पश्चिमी देशों ने विरोध जताया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि भारत के लिए रूस की मैत्री बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अपने मैत्री-मूल्यों को किसी भी दबाव में कमतर नहीं होने देगा। भले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस यात्रा पर अपनी निराशा जाहिर करते हुए इसे शांति प्रयासों को झटका तक बता चुके हो या अमेरिका ने भी यात्रा को लेकर अपनी चिंता जता दी हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी युद्ध विरोधी सोच के चलते ही यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस नहीं गए थे। दोनों देशों के बीच होने वाली सालाना द्विपक्षीय शिखर बैठक भी 2022 के बाद से नहीं हो पाई थी। इससे रूस के कुछ हलकों में यह धारणा बनने लगी थी कि भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभाव में रूस से दूरी बनाए रखना चाहता है। दुनिया में बन रही इस नई धारणा को तोड़ना जरूरी था, इसी दृष्टि से इस यात्रा के पीछे जहां द्विपक्षीय रिश्तों को संदेहों और अविश्वासों से मुक्त करने का ध्येय था, वहीं अंतरराष्ट्रीय हलकों में यह स्पष्ट संदेश भेजना था कि भारत को किसी तरह के दबाव के जरिए इस या उस पक्ष में झुकाना संभव नहीं है।

खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति पूतिन के साथ बातचीत में इसका जिक्र किया कि उनके रूस आने पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। दुनिया भर में इस यात्रा को गहरी उत्सुकता से देखा जा रहा है। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात को ध्यान में रखें तो यह कोई अचरज वाली बात भी नहीं है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का जोर इस बात पर रहा है कि भारत रूस से अपनी करीबी खत्म करे। भारत अब एक स्वतंत्र ताकत है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, बड़े शक्तिशाली देशों के लिये भी भारत एक बाजार है। इसलिये भारत किसी भी दबाव में न आते हुए शुरू से ही यह स्पष्ट कर रखा है कि वह अपने राष्ट्रहित पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा। रूस समर्थकों ने भले ही यह दर्शाना चाहा हो कि मोदी की यात्रा से भारत ने पश्चिम को चुनौती दी है और इससे पश्चिमी देश 'ईर्ष्या से जल रहे हैं', परंतु असल में भारत ऐसा कोई मंतव्य नहीं रखता है।

यह यात्रा अनेक कारणों एवं दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण रही, यात्रा के दौरान दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने के समझौते तो हुए ही, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र राष्ट्र को मैत्रीपूर्ण सलाह देते हुए पूरी बेबाकी से कहा, 'युद्ध के मैदान से कोई हल नहीं निकलता।' यह प्रधानमंत्री मोदी का वैसा ही बयान है जैसा दो साल पहले समरकंद में पूतिन से बातचीत के दौरान उन्होंने दिया था कि 'यह युद्ध का दौर नहीं है'। असल में भारत हमेशा से शांति के उजालों एवं युद्ध के अंधेरों से मुक्ति का ही समर्थक रहा है। भारत की स्पष्ट मान्यता है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत ने बम-बंदूक के बजाय शांति-वार्ता के जरिये समाधान की बात दोहराई। मोदी ने साहस एवं निर्भयता से पुतिन को दो टूक कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं। चूंकि भारतीय प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा के मौके पर ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के अस्पताल को भी निशाना बनाया, इसलिए उन्होंने बिना किसी संकोच यह भी कह दिया कि युद्ध या संघर्ष अथवा आतंकी हमलों में जब मासूम बच्चों की मौत होती है तो हृदय छलनी हो जाता है। देखना यह है कि यूक्रेन युद्ध पर भारतीय प्रधानमंत्री की फिर से खरी बात पर रूसी राष्ट्रपति कितना ध्यान देते हैं, लेकिन भारत को रूस के साथ अपनी मित्रता जारी रखते हुए यह स्पष्ट करते रहना होगा कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को यथाशीघ्र समाप्त होते हुए देखना चाहता है। यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व शांति के भी हित में है। इसी के साथ भारत ने अपने मित्र देश को अपनी तकलीफ को साझा करते हुए यह एहसास दिलाने की भी कोशिश की गई कि चीन के साथ उसकी नजदीकी परोक्ष रूप से पाकिस्तान को उत्साहित करती है, जो भारतीय जमीन पर आतंकी गतिविधियों को खाद-पानी मुहैया कराने का काम करता है।

रूस भारत के सहयोग के लिये तत्पर रहता है, इसबार भी यह खबर भी सुकून देने वाली है कि रूस ने भारत के आग्रह पर न केवल रूसी सेना के सपोर्ट स्टाफ के रूप में भारतीयों की नियुक्ति रोकना स्वीकार कर लिया है बल्कि नियुक्त किए जा चुके युवाओं को स्वदेश भेजने पर भी मान गया है। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा सफल कूटनीति के एक उत्तम उदाहरण के रूप में याद रखी जाएगी। भारतीय हितों की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व मानवता की बात करना इसी रणनीति का हिस्सा था। अन्य पहलू है, इस द्विपक्षीय रिश्ते में कौन-कौन से नए क्षेत्र शामिल किए जा सकते हैं, ताकि यह संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके। विज्ञान-प्रौद्योगिकी और 'पीपुल-टु-पीपुल कॉन्टैक्ट' यानी आम लोगों के स्तर पर आपसी संबंध को आगे बढ़ाने पर रजामंदी को इसी नजरिये से देखा जाना चाहिए। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से आने वाली दिक्कतों को दूर करना। भुगतान की टिकाऊ व्यवस्था पर जोर इसकी एक बानगी है। अच्छी बात यह भी रही कि ईंधन के मामले में भारत को स्थिरता प्रदान करने में रूसी योगदान की प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर सराहना की, जो उचित भी था, क्योंकि अब हम खाड़ी देशों के बजाय सबसे अधिक तेल रूस से ही आयात करने लगे हैं।

भारत-रूस की मैत्री का व्यापक महत्व है। यह पुराना मित्र देश का भारत की ताकत रहा है, मार्गदर्शक रहा है, हर सुख-दुःख का साथी रहा है। नेहरु युग से ही भारत-रूस के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। दोनों देशों की संस्कृति, संगीत, कला, साहित्य के बीच भी गहरा आत्मीय लगाव रहा है। भारतीय फिल्में रूस में बड़े चाव से देखी जाती रही है।

कश्मीर के मसले पर भारत जब-जब अलग-थलग पड़ता रहा, तब तब रूस ने भारत का साथ दिया। 1955 में रूस के राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव ने कश्मीर पर भारतीय संप्रभुता के लिए समर्थन की घोषणा करते हुए कहा था, 'हम इतने करीब हैं कि अगर आप कभी हमें पहाड़ की चोटियों से बुलाएंगे तो हम आपके पक्ष में खड़े होंगे।' आश्वासन सिर्फ मुंहजबानी नहीं था बल्कि सोवियत संघ ने 1957, 1962 और 1971 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों को वीटो कर दिया था, जिसमें कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की बात कही गई थी। भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान भी जब पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका भारत पर लगभग आक्रमण करने ही वाला था, तब रूस द्वारा भारत के पक्ष में भेजी गई सैन्य सहायता ने ही अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर किया था। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी रूस का अनूठा योगदान रहा है। रूस ने ही भारत को सैन्य हथियारों व अन्य साजोसामान की आपूर्ति करके अपने दुश्मनों का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ बनाया है। ऐसे भरोसेमंद देश के साथ जब बीच के दौर में आर्थिक कारणों व वैश्विक दबावों के चलते दूरी आने लगी थी तो दोनों ही देशों की जनता ने मांग उठायी कि ऐसे विश्वसनीय सहयोगी को खोना उचित नहीं होगा। मोदी की यात्रा से भारत-रूस संबंधों एवं मित्रता की नई इबारत लिखी गयी है, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम सुखद होने वाले हैं।

नजरिया

संतों के सान्निध्य में आत्म-विकास का अवसर चातुर्मास

डॉ. दिलीप धींग

मो.: 9952048107

जिस धरती पर सन्तों का प्रवास, विचरण और विहार होता है, वह धरती तथा वहाँ का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। तीर्थंकर भगवान के बारे में कहा जाता है कि वे जहाँ-जहाँ विचरण करते हैं, वहाँ रोग, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उपद्रव आदि शान्त-उपशान्त या नष्ट हो जाते हैं; वातावरण अनुकूल बन जाता है। आगमों में तीर्थंकर परमात्मा को भी श्रमण, मुनि, अनगार, भिक्षु आदि कहा गया है। एक दृष्टि से नवकार महामंत्र का पहला पद श्रमणत्व का बोधक भी है। दूसरे पद को छोड़कर नवकार के चार पदों में विभिन्न श्रेणियों में साधुत्व को भी नमस्कार है। इस तथ्य में मुनित्व और सन्तत्व की महिमा परिलक्षित होती है। तीर्थंकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होते हैं। उनका अलौकिक, अचिन्त्य प्रभाव उनके समय में तो होता ही है, उनके बाद भी होता है। उनकी वाणी और उनके नाम-सुमिरन का प्रभाव भी होता है। साधु-साध्वी ऐसे तीर्थंकर परमात्मा और उनकी महान परम्परा के अनुगामी होते हैं। निश्चित ही, उनका भी अपना प्रभाव होता है। उनके त्याग, संयम, तप, साधना आदि का प्रभाव होता है। यही वजह है कि साधु साध्वियों के आगमन से भी वातावरण अनुकूल बन जाता है, बन जाना चाहिये।

तीर्थंकर भगवान ने चार तीर्थ की स्थापना की। उन्होंने साधु-साध्वी को तीर्थ कहा तो श्रावक-श्राविका को भी तीर्थ कहा। तीर्थ यानी जो तिराये। तीर्थंकरों की प्रत्यक्ष अनुपस्थिति में उनके चार तीर्थ ही अध्यात्म मार्ग को आगे बढ़ाते हैं। सन्तों का प्रवेश और प्रवास किसी भी नगर के लिए तब जाकर अधिक प्रभावशाली बन जाता है, जब वहाँ वे निवासी तीर्थ-तुल्य श्रावक-श्राविका और गृहस्थजन स्वयं अपनी साधना करते हुए सन्तों की साधना में सहभागी बने। संघीय व्यवस्था का यही महत्व है कि इसमें एक और एक दो नहीं, अपितु ग्यारह हो जाते हैं।

प्राकृत आगम जीवाजीवाभिगम सूत्र में उल्लेख

है कि साधु-साध्वी और श्रावक-श्राविका की साधना, व्रत-नियम, जप-तप, ब्रह्मचर्य आदि से निसृत सकारात्मक ऊर्जा के कारण सागर अपनी मर्यादा में रहता है तथा अन्य आपदाएँ नहीं आती हैं। सन्तों के आगमन से गृहस्थजनों के नैतिक आध्यात्मिक जीवन को बल मिलता है। हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। कोई स्वयं साधना में संलग्न हो जाते हैं तो कोई दूसरों का सहयोग करते हैं। ज्ञान-ध्यान और आत्म-साधना का एक सकारात्मक, सहयोगात्मक और सहकारितापूर्ण वातावरण बन जाता है। जो ऐसे वातावरण से जुड़ते हैं, उनके जीवन के अनेक अशुभ टल जाते हैं या वे शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं।

इतिहास के पृष्ठों पर संतों के पदार्पण और प्रवास के सुप्रभाव के अनेक प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं। जैन इतिहास में एक अद्भुत प्रसंग मिलता है। उन दिनों जैनाचार्य वादीदेवसूरि (12वीं सदी) नागपुर में विराजमान थे। गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह ने नागपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई और आक्रमण के लिए नागपुर के बाहर तक पहुँच गये। जब उन्हें पता चला कि नागपुर में जैनाचार्य वादीदेव विराजमान है तो वे बिना आक्रमण किये अपनी सेना को लेकर पुनः गुर्जर-प्रदेश लौट गये।

बीसवीं सदी के पूर्वार्ध का एक ऐसा ही प्रेरक प्रसंग है। तब जैन दिवाकर चौथमलजी महाराज ग्राम डूंगला (चित्तौड़गढ़-राजस्थान) में विराजमान थे। उस समय कुछ डाकू डूंगला पर डाका डालना चाहते थे। वे जब डूंगला के निकटवर्ती ग्राम बिलोदा तक पहुँचे तब उन्हें पता चला कि डूंगला में जैन दिवाकर मुनि चौथमलजी विराजमान हैं। इस जानकारी पर उन्होंने डाका डालने का विचार त्याग दिया। बाद में उन खूंखार डाकुओं ने हमेशा के लिए डकैती का धंधा ही छोड़ दिया। आचार्य हुक्मीचन्दजी महाराज के जीवन की घटना है।

एक ग्राम में महामारी फैली हुई थी। उस समय चिकित्सा सुविधाएँ भी अपर्याप्त थीं। आये दिन बड़ी संख्या में लोग मर रहे थे। स्वस्थ आदमी को प्रतिपल संक्रमण का खतरा बना रहता था। ऐसे ग्राम में भी आचार्यश्री बिना किसी भय के पधारे। उस गाँव में उनके प्रवेश के बाद एक भी व्यक्ति अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बना। कर्नाटक गजकेसरी तपस्वी गणेशलालजी महाराज के जीवन में भी साधना के सुप्रभाव की अनेक घटनाएँ मिलती हैं। सन्तों की साधना के अचिन्त्य प्रभाव के अनेक प्रेरक प्रसंग इतिहास और जनश्रुतियों में पढ़ने-सुनने को मिल जाते हैं।

सन्तों के प्रवेश और प्रवास को उसी उम्मीदभरे अनुकूल एहसास के रूप में लेना चाहिये। मानव-जीवन की सार्थकता बोध तथा अहिंसा का ज्ञान जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सन्तों के आगमन से यदि यह बोध व ज्ञान अधिक से अधिक जनों में जागृत होता है तो समाज व देश के लिए यह वरदान है।

सन्तों के प्रवेश के साथ ही यदि सबके हृदय में श्रद्धा, मैत्री और सद्भाव का प्रवेश होता है और नकारात्मक भावों का निष्कासन होता है तो वैसा प्रवेश सार्थक है। सन्तों का पदार्पण यानी कुएँ का प्यासे के पास जाना। मैंने अपनी बाल कविता में संतों को ''ठंडे जल से भरे कलश'' की उपमा देते हुए लिखा है-

सूने मन में वसन्त लाते,
इसीलिए ये सन्त कहाते।
पाँच व्रतों की महिमा वाला,
पंचरंगी झण्डा फहराते।
ठंडे जल से भरे कलश ये
प्यासों के नजदीक आये हैं।

सन्तों के प्रवेश और प्रवास को अधिक फलदायी व यादगार बनाने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर आध्यात्मिक संकल्प किये जा सकते हैं। राजकीय स्तर पर अहिंसा की घोषणा करवाई जा सकती है। विशाल मेवाड़ रियासत (वर्तमान में दक्षिणी राजस्थान) के अन्तर्गत आने वाले किसी भी ग्राम या नगर में जब जैन दिवाकर चौथमलजी महाराज का प्रवेश और विहार होता था, तो उन दिनों में वहाँ शासकीय स्तर पर अगता (अहिंसा-दिवस) का अनुपालन होता था। सभी बूचड़खाने और मदिरालय कानूनन बन्द रहते थे। जैन दिवाकरजी के समय में अन्य रियासतों, राजाओं, जागीरदारों और नवाबों की ओर से भी इस आशय के राजकीय आदेश प्रसारित होते थे तथा उनका पूर्ण अनुपालन होता था। वर्तमान में भी अहिंसा के सत्संकल्प के साथ सन्तों की अगवानी की जा सकती है। श्रेष्ठ परम्पराओं तथा परम्परा की श्रेष्ठताओं को अपनाना और उन्हें आगे बढ़ाना सबका पुनीत कर्तव्य है।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

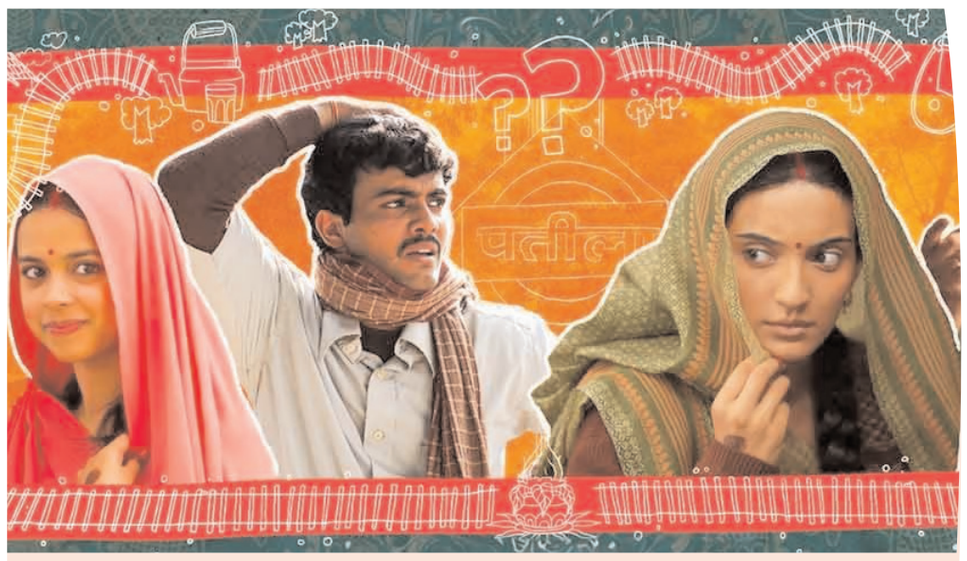

‘लापता लेडीज’ और ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ आईएफएफएम 2024 के लिए नामांकन में सबसे आगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। किरण राव की ‘लापता लेडीज’, करण जौहर द्वारा निर्देशित ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’, विधु विनोद चोपड़ा की ‘12वीं फेल’ और जियो बेबी की ‘कथल-द कोर’ आगामी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) अवार्ड्स 2024 में शीर्ष नामांकित फिल्मों के रूप में उभरी हैं। आयोजकों ने बुधवार को यह जानकारी दी। आईएफएफएम का 15वां संस्करण 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू होगा और 25 अगस्त तक चलेगा।

विजेताओं की घोषणा 16 सितंबर को मेलबर्न के पालाइस थिएटर में आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में की जाएगी। ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ और ‘12वीं फेल’ के अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में ‘अमर सिंह चमकीला’, ‘चंदू चैंपियन’, ‘डंकी’, ‘जवान’, ‘महाराजा’ और ‘प्रेमलु’ भी नामांकित हैं।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में शाहरुख खान को ‘डंकी’ और ‘जवान’ के लिए दोहरा नामांकन मिला है। दिलजीत दोसांझ (अमर सिंह चमकीला), फहद फासिल (आवेशम), कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन), ममूटी (कथल द कोर), मिथुन चक्रवर्ती (काबुलीवाला), रणवीर सिंह (रॉकी और रानी की प्रेम कहानी), स्पर्श श्रीवास्तव (लापता लेडीज़), विक्की कौशल (सैम बहादुर) और विक्रांत मैसी (12वीं फेल) भी शीर्ष पुरस्कार के लिए दौड़ में हैं। ‘लापता लेडीज़’ से अभिनय की शुरूआत करने वाली अभिनेत्री नितांशी गोयल और प्रतिभा रांटा तथा अलीजेह अग्निहोत्री (फर्रे) को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकन मिला है।

रूस से रिश्तों को लेकर चिंताओं के बावजूद रणनीतिक साझेदार बना रहेगा भारत : अमेरिका

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वाशिंगटन/भाषा। अमेरिका के जो बाइडन प्रशासन ने कहा है कि रूस के साथ संबंधों को लेकर चिंताओं के बावजूद भारत वाशिंगटन का रणनीतिक साझेदार बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22वीं भारत-रूस शिखर वार्ता के लिए मॉस्को के दो दिवसीय दौरे पर गए थे। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बातचीत पर पश्चिमी देशों की करीबी नजर थी।

मंगलवार को पुतिन से बातचीत में मोदी ने उनसे कहा कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान पर संभव नहीं है और शांति के प्रयास बम और बुलेट के बीच सफल नहीं होते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन और विदेश विभाग के प्रवक्ताओं ने रूस के साथ भारत के रिश्तों और मोदी के मॉस्को दौरे से जुड़े सवालों पर मंगलवार को अलग-अलग प्रतिक्रिया दी। पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने वाशिंगटन में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, भारत और रूस के बीच काफी लंबे समय से रिश्ते हैं। अमेरिका के नजरिये से, भारत एक रणनीतिक साझेदार है, जिसके साथ हम रूस से उसके रिश्तों को लेकर पूर्ण और स्पष्ट बातचीत करना जारी रख रहे हैं। चूंकि, यह इस हफ्ते होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से संबंधित है, इसलिए निश्चित रूप से, आपकी तरह ही दुनिया का ध्यान भी इस पर केंद्रित है। वहीं दूसरी ओर, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिका रूस से भारत के रिश्तों को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहा है। उन्होंने कहा, हमने अपनी चिंताओं को निजी तौर पर सीधे भारत सरकार के समक्ष जाहिर किया है और हम ऐसा करना जारी रख रहे हैं। इसमें बदलाव नहीं हुआ है।

भारत ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की अभी तक निंदा नहीं की है। वह लगातार बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के समाधान की वकालत करता आया है। राइडर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अगर (रूस के) राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस यात्रा (मोदी का रूस दौरा) को कुछ ऐसे पेश करें, जिससे किसी तरह यह दिखाया जा सके कि वह बाकी दुनिया से अलग-थलग नहीं हैं, तो कोई भी आश्चर्यचकित होगा।

सच तो यह है कि राष्ट्रपति पुतिन के युद्ध का विकल्प चुनने से रूस बाकी दुनिया से अलग-थलग हो गया है और उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। राइडर ने कहा, उन्हें आक्रामकता की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है और तथ्य इस बात की गवाही देते हैं। इसलिए, हम भारत को रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखना जारी रखेंगे। हम उनके साथ ठोस बातचीत करना जारी रखेंगे।

रूस ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक, परिवर्तनकारी बताया

नई दिल्ली/भाषा। रूस के दूतावास प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मॉस्को की दो दिवसीय यात्रा और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी शिखर वार्ता अशांत भूराजनीतिक माहौल को देखते हुए ‘‘ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी’’ रही। उन्होंने मोदी और पुतिन की शिखर वार्ता के एक दिन बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर थी जिससे यह स्पष्ट है कि यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण थी।

रूसी राजनयिक ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत में भारत-रूस व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। शिखर वार्ता की प्रमुख बातों पर प्रकाश डालते हुए बाबुश्किन ने कहा कि भारत और रूस ने राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल करने वाली द्विपक्षीय भुगतान प्रणाली को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों की वापसी की भारत की मांग पर उन्होंने कहा, ‘‘हम इस मुद्दे पर भारत से सहमत हैं।’’ यह पूछे जाने पर कि भारतीय स्वदेश कब लौटेंगे, बाबुश्किन ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि इसे जल्द ही हल कर लिया जाएगा।’’

हम कभी सेना में भारतीयों को भर्ती नहीं करना चाहते थे, मुद्दे के शीघ्र समाधान की उम्मीद है : रूस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। रूस ने बुधवार को कहा कि वह रूसी सेना में सहायक कर्मी के रूप में भर्ती किये गए भारतीयों की वापसी के भारत के आह्वान से संबंधित मुद्दे के शीघ्र समाधान की उम्मीद कर रहा है। उसने कहा कि उनकी भर्ती पूरी तरह से एक व्यावसायिक मामला है।

रूसी सरकार की ओर से इस मुद्दे पर पहली टिप्पणी में, रूस के दूतावास प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने कहा कि मॉस्को कभी नहीं चाहता था कि भारतीय उसकी सेना का हिस्सा बनें और संघर्ष के संदर्भ में उनकी संख्या नगण्य है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में मीडियाकर्मियों से कहा, ‘‘हम इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ हैं। हमें उम्मीद है कि इस मुद्दे का जल्द समाधान होगा।’’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया, जिसके बाद रूस ने रूसी सेना में सहायक कर्मियों के रूप में कार्यरत भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने का वादा किया था और इसके एक दिन बाद बाबुश्किन का बयान आया।

बाबुश्किन ने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हम पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि हमने कभी नहीं चाहा कि भारतीय रूस की सेना में शामिल हों। आप इस पर रूस के अधिकारियों द्वारा कभी कोई घोषणा नहीं देखेंगे।’’ रूसी राजनयिक ने कहा कि ज्यादातर भारतीयों की नियुक्ति एक ‘कमर्शियल फ्रेमवर्क’ के तहत की गई थी क्योंकि वे धन अर्जित करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भारतीयों की 50, 60 या 100 संख्या, व्यापक संघर्ष के संदर्भ में कोई महत्व नहीं रखती। उन्होंने कहा, ‘‘वे विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक कारणों से आए थे और हम उन्हें भर्ती नहीं करना चाहते थे।’’ बाबुश्किन ने कहा कि सहायक कर्मी के रूप में भर्ती अधिकतर भारतीय अवैध तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काम करने के लिए उपयुक्त वीजा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनमें से अधिकतर पर्यटक वीजा पर रूस आए थे। मारे गए लोगों के परिजनों को क्या मुआवजा और रूसी नागरिकता दी जाएगी, इस सवाल के जवाब में बाबुश्किन ने कहा कि ऐसा तो संविदा की प्रतिबद्धताओं के अनुसार वैसे भी होना चाहिए।

विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने मंगलवार को मॉस्को में कहा था कि रूस ने अपनी सेना में सेवारत सभी भारतीय नागरिकों को जल्द मुक्त करने का वादा किया है।

धन शोधन मामला : ईडी के समक्ष पेश नहीं हुईं जैकलीन फर्नांडिस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े धन शोधन मामले में नये दौर की पूछताछ के लिए बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं हुईं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। फोर्टिस हेल्थकेयर कंपनी के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह सहित कई अन्य मशहूर लोगों से कथित तौर पर लगभग 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में 38 वर्षीय जैकलीन से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है।

ईडी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने ‘अपराध से अर्जित रकम’ या अवैध धन का इस्तेमाल श्रीलंका मूल की बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन के वास्ते तोहफे खरीदने के लिये किया था।

सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने मामले में कुछ नई जानकारियां जुटाई हैं इसलिए उन्होंने जैकलीन को आज (बुधवार को) पूछताछ के लिए तलब किया था। अभिनेत्री एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुईं हालांकि उनकी कानूनी टीम ने ईडी अधिकारियों से मुलाकात की और बताया कि वह ‘स्वास्थ्य समस्याओं’ के कारण पेश होने में असमर्थ हैं।

ईडी जल्द ही उन्हें दोबारा समन जारी कर सकती है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2022 में दायर एक आरोपपत्र में कहा था कि जैकलीन चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास से अवगत होने के बावजूद उससे कीमती सामान, आभूषण और महंगे तोहफे लेती थीं।

मामले में ईडी जैकलीन से कम से कम पांच बार पूछताछ कर चुकी है।

जैकलीन का कहना है कि वह बेकसूर हैं और उन्हें चंद्रशेखर की कथित आपराधिक गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

जम्मू कश्मीर ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए समिति बनायी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 13 वर्ष से इस केंद्र शासित प्रदेश (पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य) में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए सात सदस्यीय एक समिति बनायी है जिसका लक्ष्य उन्हें उनके देश में भेजने को सुगम बनाना है। इस समिति को अवैध शरणार्थियों की पृष्ठभूमि और ‘बायोमेट्रिक’ विवरण एकत्र करने तथा नियमित रूप से उसका अद्यतन डिजिटल रिकॉर्ड बनाये रखने का काम सौंपा गया है।

सरकार के प्रधान सचिव (गृह विभाग) चंद्रकेर भारती ने एक आदेश में कहा, ‘‘2011 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से अधिक समय से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए समिति के पुनर्गठन की मंजूरी दी जाती है।’’ गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि पंजाब के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, जम्मू और श्रीनगर के अपराध जांच विभाग (विशेष शाखा) कार्यालयों के संबंधित अधिकारी, सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (विदेशी पंजीकरण) एवं एनआईसी के राज्य समन्वयक उसके सदस्य होंगे। सरकारी आदेश के मुताबिक समिति को मासिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी और हर महीने पांचवें दिन उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपनी होगी। गृह विभाग ने समिति को इस केंद्रशासित प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने और उन्हें उनके देश में भेजने के प्रयासों में तालमेल कायम करने एवं इस प्रक्रिया पर निगरानी रखने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा समिति इन मुद्दों पर हुई प्रगति की निगरानी करेगी तथा गृहविभाग को नियमित रूप से रिपोर्ट करेगी।

ऑस्ट्रेलियाई एम्बर ने करोड़ों साल पहले गोंडवाना में पाए गए ‘जीवित जीवाश्म’ का खुलासा किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

सिडनी/द कन्वरसेशन। एम्बर जीवाश्म वृक्ष राल में संरक्षित होते हैं। भूमि या समुद्र में पाए जाने वाले पारंपरिक जीवाश्मों के विपरीत, एम्बर प्राचीन जीवन रूपों को अविश्वसनीय विस्तार से संरक्षित कर सकता है। इसे अक्सर दुनिया भर में जीवाश्म विज्ञान की पवित्र कब्र माना जाता है। एम्बर एक टाइम कैप्सूल की तरह काम करता है, जो लाखों साल पहले के छोटे जानवरों, पौधों और यहां तक कि सूक्ष्मजीवों को भी पकड़ लेता है। ये जीवाश्म – जिन्हें समावेशन के रूप में भी जाना जाता है – आश्चर्यजनक रूप से ताजा, संरक्षित दिखाई दे सकते हैं जैसे वे तब थे जब वे पेड़ की चिपचिपी राल में फंसकर मर गए थे। ऑस्ट्रेलियाई एम्बर अब चार करोड़ 20 लाख वर्ष पहले के प्राचीन गोंडवानन वातावरण की जैविक विविधता और आज के ऑस्ट्रेलियाई जंगलों से उनके संबंधों को समझने में मदद कर रहा है। इससे हम और भी कारण जान सकते हैं कि हमें आज के वनों की रक्षा क्यों करनी चाहिए।

ऑस्ट्रेलियाई एम्बर का अद्वितीय मूल्य : विशिष्ट, कुचली हुई जीवाश्म चट्टान आकृतियों के विपरीत, जीवाश्म विज्ञानी एम्बर को पूर्ण तीन आयामों में समावेशन को संरक्षित करने की उल्लेखनीय क्षमता के लिए महत्व देते हैं। इसका मतलब है कि हम उन जीवाश्म जीवों का अध्ययन कर सकते हैं जिन्हें अन्यथा इतने विस्तार से दर्ज नहीं किया गया होता। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक जैव विविधता का लगभग 85% आर्थ्रोपोड्स (मकड़ियों, मक्खियों, बीटल, मधुमक्खियों और इसी तरह के जीव) से आता है। केवल 0.3% का प्रतिनिधित्व हड्डी वाले स्तनधारियों द्वारा किया जाता है जो आमतौर पर चट्टानों में जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर, संपूर्ण भूगर्भिक काल में समस्त जीवन का केवल एक छोटा सा अंश ही जीवाश्म बन पाया है। इसका मतलब है कि हम एक पक्षपाती जीवाश्म रिकॉर्ड के साथ काम करते हैं जो पिछली विविधता का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। एम्बर कम आम नमूनों को खोजने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह पिछले पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को प्रकट करने और प्राचीन जीवन की हमारी समझ में इन पूर्वाग्रहों को कम करने में मदद करता है।

अधिकांश एम्बर खोजें उत्तरी गोलार्ध (बाल्टिक क्षेत्र, स्पेन, चीन, म्यांमार) से आती हैं। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां वैज्ञानिक एम्बर में फंसे जीवों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इ न संरक्षित जीवों को खोजने

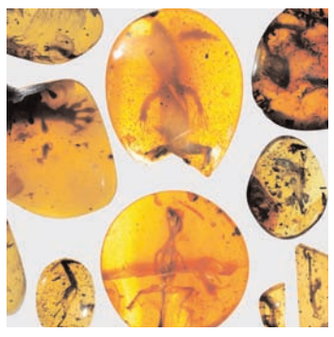

के लिए सबसे आशाजनक स्थल विक्टोरिया का पूर्व कोयला खनन क्षेत्र है। इस स्थल से प्राप्त एम्बर और जीवाश्म 4 करोड़ 20 लाख-4 करोड़ वर्ष पुराने होने का अनुमान है, जो इओसीन युग के हैं। उस समय, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका अभी भी गोंडवाना नाम के धीरे-धीरे खंडित होने वाले महाद्वीप के हिस्से के रूप में जुड़े हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में गर्म और नम जलवायु थी, और जंगल कीड़े, अरचिन्ड और अन्य प्राणियों से भरे हुए थे।

जीवित जीवाश्म : हम जिस एम्बर के साथ काम कर रहे हैं, उसका अध्ययन 2014 से शोधकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। 2020 में वर्णित निष्कर्षों में बिटिंग मिडज, बेबी स्पाइडर और मिलाप में मगन मक्खियों की जोड़ी भी शामिल है। हमारा नवीनतम कार्य प्रजातियों पर अधिक विवरण प्रकट करता है। हमने न केवल यह सीखा है कि ये जीव अतीत में कहाँ रहते थे, बल्कि आश्चर्यजनक तथ्य है कि उनमें से कई आज भी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में मौजूद हैं, यद्यपि बहुत कम भौगोलिक सीमाओं में। इसका मतलब है कि प्राचीन गोंडवाना के जीव चार करोड़ से अधिक वर्षों से मौजूद हैं। इतने लंबे समय तक उनका जीवित रहना उन्हें भविष्य में सुरक्षित रखने का और भी बड़ा कारण देता है। हमारे शोध में बड़ी सफलता मेलबर्न में एएनएसटीओ की ऑस्ट्रेलियाई सिंक्रोट्रॉन अनुसंधान सुविधा में नई प्रगति पर आधारित है। बेहतर रिज़ॉल्यूशन और एक्स-रे के साथ छोटे नमूनों को स्कैन करने की क्षमता में काफी सुधार हुआ है कि हम एम्बर में फंसे जीवों की छवियां कैसे बना सकते हैं। यह हमें विस्तृत 3डी पुनर्निर्माण बनाने की क्षमता देता है, और हम प्रजातियों की अधिक आसानी से पहचान कर सकते हैं।

मुकेश अंबानी ने बेटे की शादी का पहला निमंत्रण बांके बिहारी को भेजा

मथुरा (उप्र)/भाषा। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अपने पुत्र अनंत की शादी का पहला निमंत्रण मंगलवार को वृन्दावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी को भेजा और उनसे पुत्र एवं पुत्रवधू को आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। उद्योगपति के प्रतिनिधियों ने मंदिर के सेवायत पुजारी आचार्य गोपी गोस्वामी एवं श्रीनाथ गोस्वामी से भेंट कर ठाकुरजी को निमंत्रण पत्र दिया। गोस्वामी ने बताया कि प्रतिनिधियों ने पूर्ण वैदिक परंपरा के अनुसार मंत्रोच्चार के बीच मुकेश अंबानी द्वारा भेजा गया निमंत्रण ठाकुरजी के चरणों में रखा और उनसे अंबानी परिवार पर कृपा बनाए रखने तथा पुत्र एवं पुत्रवधू को आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा उद्योगपति ने बेटे की शादी का निमंत्रण बांके बिहारी के साथ-साथ स्वामी हरिदासीय संप्रदाय से जुड़े टटिया स्थान आश्रम को भी भेजा है। गोस्वामी ने बताया कि वह ठाकुरजी की ओर से अंबानी के पुत्र की शादी में शामिल होने अपने अनुज श्रीनाथ गोस्वामी के साथ मुंबई जाएंगे और विवाह के अवसर पर अंबानी परिवार को ठाकुर जी के आशीर्वाद स्वरूप प्रसादी व अंगवस्त्र भेंट करेंगे। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी 12 जुलाई को मुंबई में राधिका मर्चेंट के साथ होगी।

रसोई गैस के फर्जी ग्राहकों की पहचान के लिए ई-केवाईसी सत्यापनः पुरी

नई दिल्ली/भाषा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां फर्जी उपभोक्ताओं को हटाने के लिए रसोई गैस ग्राहकों का आधार के जरिये ई-केवाईसी सत्यापन कर रही हैं। आधार की मदद से ई-केवाईसी (ऑनलाइन ग्राहक सत्यापन) की प्रक्रिया उन फर्जी ग्राहकों को अलग करने के लिए की जाती है जिनके नाम पर बुक कराई गई रसोई गैस का इस्तेमाल वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है। परिवारों को 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर 803 रुपये (लगभग 56.5 रुपये प्रति किलोग्राम) की दर से खरीदना पड़ता है जबकि होटल एवं रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 19 किलोग्राम का वाणिज्यिक सिलेंडर 1,646 रुपये (86.3 रुपये प्रति किलोग्राम) में मिलता है। पुरी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘‘पेट्रोलियम विपणन कंपनियां एलपीजी ग्राहकों के लिए आधार के माध्यम से ईकेवाईसी सत्यापन कर रही हैं, ताकि उन फर्जी ग्राहकों को हटाया जा सके, जिनके नाम पर कुछ गैस वितरक अक्सर वाणिज्यिक सिलेंडर बुक करते हैं। यह प्रक्रिया आठ महीने से अधिक समय से लागू है।’’

गंभीर के वेतन के करार पर अभी हस्ताक्षर नहीं, पहली बड़ी परीक्षा होगी ऑस्ट्रेलिया में

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के तौर पर गौतम गंभीर की नियुक्ति की वित्तीय औपचारिकतायें अभी पूरी की जानी बाकी हैं लेकिन इस समय उनके लिए सबसे अहम चीज तीन साल के कार्यकाल के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार होने के मद्देनजर पसंदीदा सहयोगी स्टाफ रखना है।

मंगलवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) सचिव जय शाह ने आधिकारिक रूप से गंभीर की नियुक्ति की घोषणा की जिसका लंबे समय से पूर्वानुमान लगाया जा रहा था। हालांकि पता चला है कि उनका वेतन अभी तय किया जाना बाकी है, हालांकि यह उनके पूर्ववर्ती राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री के समान होने की उम्मीद है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, ‘‘गौतम के लिए जिम्मेदारी संभालना ज्यादा महत्वपूर्ण था, वेतन और अन्य चीजों पर काम किया जा सकता है। यह 2014 में रवि शास्त्री जैसा मामला ही है जिसमें उन्हें पहली बार मुख्य कोच डंकन फ्लेचर की जगह क्रिकेट निदेशक बनाया गया था। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘जिस दिन रवि जुड़े थे, उनका तो अनुबंध भी नहीं था और चीजें बाद में पूरी की गईं। गौतम के मामले में भी, कुछ बारिकियों पर काम जारी है। उनका वेतन राहुल द्रविड़ के समान ही होगा। ’’ पता चला है कि गंभीर को काम करने के लिए अपनी टीम मिलेगी जो एनसीए (राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी) के कोचों के साथ मिलकर काम करेंगे। गंभीर ने कहा था, ‘‘क्रिकेट मेरा जुनून है और बीसीसीआई, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण, सहयोगी स्टाफ और सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करने को लेकर मैं उत्सुक हूं क्योंकि हम आगामी टूर्नामेंटों में सफलता हासिल करने की दिशा में काम करेंगे।’’ लक्ष्मण इस समय युवा टी20 टीम के साथ जिम्बाब्वे में हैं लेकिन उम्मीद है कि जब वह वापस लौट आयेंगे तो वह नये कोच, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, दो कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पंड्या के साथ मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। गंभीर के कोर सहयोगी स्टाफ में कौन होगा, इसको लेकर भी काफी दिलचस्पी बनी हुई है। केकेआर अकादमी के प्रमुख अभिषेक नायर के इसमें शामिल होने के कयास लग रहे हैं जो आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर के अहम रणनीतिकारों में से एक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा के करीब दोस्तों में शामिल हैं। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने एल बालाजी और जहीर खान का नाम गेंदबाजी कोच के लिए दो संभावित उम्मीदवारों के तौर पर पेश किया है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

www.dakshinbharat.com
epaper.dakshinbharat.com

चेन्नई | गुरुवार | 11-07-2024 /dakshinbharat /dakshinbharat DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT HINDI DAILY

RNI No. : TNHIN/2013/52520
Regn No. : TN/CCN/613/2014-2016
posted at Patrika Channel,
Egmore RMS, Chennai-8

जीवन अनिश्चितताओं से भरा लंबा यात्रा-पथ है। यहां किसी के जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। हमारे मन का सोचा हुआ सब सार्थक होगा, यह मानकर चलना बहुत बड़ी भूल है। इसीलिए अच्छे अवसरों का लाभ उठाने का भरपूर प्रयत्न करना चाहिये। जीवन की सफलता का यही मूलमंत्र है। अक्सर देखा जाता है कि लक्ष्मीदेवी तिलक करने द्वार पर आयी और मनुष्य मुंह धोने के लिए चला गया। जब वह वापस लौटा, तब तक लक्ष्मी विदा हो चुकी थी। नीति और धर्मशास्त्रों ने इसे निपट मूर्खता कहा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे बोर्ड के सदस्य ने दक्षिण रेलवे का दौरा किया

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। रेलवे बोर्ड के सदस्य (इंफ्रास्ट्रक्चर) अनिलकुमार खंडेलवाल वर्तमान में दक्षिण रेलवे के दो दिवसीय दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने दक्षिण रेलवे मुख्यालय में अपर महाप्रबंधक कौशल किशोर और प्रमुख विभागाध्यक्षों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान खंडेलवाल ने विभिन्न परिचालन पहलुओं और प्रस्तावित सुधारों पर चर्चा की।

उन्होंने विशेष रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन पुनर्विकास, विद्युतीकरण परियोजनाओं, रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण, सब-वे, सड़क सुरक्षा उपायों और सिग्नल और दूरसंचार कार्यों के साथ-साथ अन्य प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, यात्री यातायात में व्यवधान को कम करने के महत्व पर जोर दिया।

समीक्षा बैठक के बाद खंडेलवाल एक विशेष ट्रेन से चेन्नई एग्मोर-विल्लुपुरम खंड का निरीक्षण करने के लिए रवाना हुए। ताम्बरम, चेंगलपट्टू और विल्लुपुरम स्टेशनों का निरीक्षण भी शामिल है।

सिद्ध परमात्मा पर श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है : युवाचार्यश्री महेंद्रऋषि

नार्थ टाऊन में धर्मसभा का आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। श्रमण संघीय युवाचार्य महेंद्र ऋषिजी महाराज आदि का बुधवार सुबह नार्थ टाऊन (बिन्नी मिल्स) के एएमकेएम भवन में आगमन हुआ। वहां प्रवचन में उन्होंने कहा कि उत्तराध्ययन के 36वें अध्ययन में भगवान महावीर ने कहा था कि तीन बातों सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के साथ किसी भी भव्य आत्मा की आयुष्य पूर्ण होती है तो वह जागृति को धर्म की शरण मिलेगी। जो व्यक्ति केवल इस जीवन को ही संपूर्ण मानता है, आगे पीछे की नहीं सोचता तो वह जानता है, यह जीवन का पड़ाव है, यह कब पूरा हो जाएगा, नहीं पता। जो यह जानता है, विश्वास रखता है, जो जागृत हैं, उसे पता है, प्रत्येक क्षण का कैसे उपयोग करना।

उन्होंने कहा जीवन के हर क्षण को सार्थक करना है तो ऐसी जागृत वाला सम्यक दर्शन से अनुराग रखने वाला हो। सम्यक दर्शन जैन धर्म, जैन दर्शन, मोक्ष मंजिल की नींव है। जब तक दर्शन नहीं, तब तक ज्ञान नहीं। जब तक ज्ञान नही, तब तक चारित्र नहीं। जब तक चारित्र नहीं, तब तक मोक्ष नहीं। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन का अर्थ, स्वरूप, आचरण को समझना जरूरी है। सम्यक यानी यथार्थ, जैसा है वैसा, सही। दर्शन यानी दृष्टि या आस्था। हमारी सही दृष्टि होनी जरूरी है। आज सब ओर अंध श्रद्धा का बोलबाला है। वहां सम्यक दर्शन की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन का मतलब है भीतर में रहे हुए सामर्थ्य को पाना। उसमें हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। वीतराग के दर्शन कर भौतिक सुख सुविधा मांगना अज्ञानता है। आप जिनके दर्शन कर रहे हो, उनके वास्तविक स्वरूप को समझो। अपने आत्म तत्व पर विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए। सिद्ध परमात्मा पर श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है।

मेरा जीवन, मेरी जीवात्मा सिद्ध जैसी निरंजन, निर्विकार, शुद्ध बने, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह अकेला होता है। वह दो पांव से चलता है, ज्ञानीजन कहते हैं विवाह कर दो के चार पांव हो जाते हैं और चार पांव वाले की हालत कैसी होती है, वह हम जानते हैं। बच्चा हो जाता है तो वह छः पांव वाला यानी भंवरा बन जाता है। फिर एक बच्चा हो गया तो आठ पांव का मकड़ी जैसा बन जाता है। इसी में उलझा हुआ जीवन होता है, जीवन इसी चक्कर में खत्म हो जाता है।

उन्होंने कहा, हमें परमात्मा के वचन में श्रद्धा होनी चाहिए। जिसकी दृष्टि सही है, उसमें श्रद्धा होती है। साधना, साधुत्व वही है। जिसकी नजर, नजरिया स्पष्ट है, वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन साधुत्व भावों में हैं, संयम के प्रति जागरूकता में है। साधुत्व पूर्णतः मन वचन और काया से भावों की निर्मलता पर निर्भर करता है। आठ प्रवचन माता से साधुत्व का पालन पोषण होता है, तभी संयम सुरक्षित रहता है। मैं आत्मा हूं, इसमें श्रद्धा है तो धर्म की शरण मिलती है। सम्यक दर्शन वही, जो खुद के लिए हो। आत्मा का सुख ही तीनों लोक में श्रेष्ठ है। जिससे अंतःकरण में प्रसन्नता हो, आनंद की भावना से जो धर्म करते हैं, वह सम्यक दर्शन है। हम सब अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ें। इस दौरान महिला मंडल ने भाव भरा स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर नार्थ टाऊन स्थानकवासी जैन संघ के अध्यक्ष अशोक एम. कोठारी, मंत्री ललित बेताला, प्रमोद ललवानी समेत कई गणमान्य उपस्थित थे। युवाचार्यश्री की अगले दो दिन नार्थ टाऊन में स्थिरता रहेगी, जहां सुबह 9 से प्रवचन होगा।

इक्कीस दिवसीय राष्ट्रीय प्राकृत शिक्षण कार्यशाला का समापन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुमलै। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं आचार्य श्री अकलंक शैक्षणिक न्यास, अरिहंतगिरि के संयुक्त तत्वावधान में तिरुवण्णामलै जिले में तिरुमलै स्थित अरिहंतगिरि में इक्कीस दिवसीय राष्ट्रीय प्राकृत शिक्षण कार्यशाला का समापन बुधवार को तमिलनाडु के राज्यपाल रवीन्द्र नारायण रवि के मुख्य आतिथ्य में हुआ। चेयरमैन भट्टारक धवलकीर्ति स्वामी और केंद्रीय संस्कृत विवि के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी ने राज्यपाल का सम्मान किया। समन्वयक प्रो. मधुकेश्वर भट ने स्वागत भाषण दिया। प्राकृत विकास अधिकारी डॉ. धर्मेन्द्रकुमार जैन ने कार्यशाला का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राज्यपाल ने अनुशीलनम' और जैन दर्शन की वैज्ञानिकता' पुस्तकों का विमोचन किया। राज्यपाल ने धवलकीर्ति एवं आचार्य श्री अकलंक शैक्षणिक न्यास की न्यासी सरिता जैन एवं समाजसेवी एमके जैन का सम्मान किया। सरिता जैन फाउंडेशन की ओर से 232 जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई। राज्यपाल ने तिरुमलै जैन पर्वत पर चढ़कर भगवान नेमीनाथ एवं कुंदवै जिनालय में दर्शन किये।

प्राकृत कार्यशाला प्रवक्ता डॉ. दिलीप धींग ने बताया कि इस कार्यशाला में आचारांग सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, पउमचरियं, प्रवचनसार, वसुदेवहिंडी आदि के अतिरिक्त अभिज्ञान शाकुंतलम् जैसे संस्कृत ग्रंथों में उपलब्ध प्राकृत पाठों का बोध भी करवाया गया। 12 साल की बालिका स्वाति शाह और छठी कक्षा की हर्षिता पतंगिया ने भी प्राकृत सीखी। जिनवाणी के संपादक प्रो. धर्मचंद जैन, प्रो. जगराम भट्टाचार्य, प्रो. दीनानाथ शर्मा, गणेश तिवारी, डॉ. सतेंद्र कुमार जैन, डॉ. प्रभात कुमार दास आदि ने अध्यापन करवाया। पालि-प्राकृत योजना के डॉ. चक्रधर मेहर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

मणिलाल मेहता गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में शपथ ग्रहण समारोह

चेन्नई/दक्षिण भारत राष्ट्रमत। स्थानीय मणिलाल एम. मेहता गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थी परिषद के निर्वाचित पदाधिकारी के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य ने स्वागत भाषण दिया। मुख्य अतिथि के रूप में तमिलनाडु मेडिसिन एंड होम्योपैथिक विभाग की आयुक्त मैथिली राजेंद्रन उपस्थित थी, जिन्होंने छात्रा परिषद का शपथ दिलवाई।

उन्होंने अपने संबोधन में छात्राओं को नेतृत्व के गुण और कर्तव्य के बारे में बताया।उन्होंने छात्रा परिषद के महत्व पर प्रकाश डाला और यह बताया कि यह मंच छात्राओं में आत्मविश्वास जगाने और उनकी प्रतिभा को निखारने का एक शानदार अवसर है।

निर्वाचित छात्रों ने अपने पद की शपथ लेकर अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा से निभाने का वचन लिया।

तिरुनीरमलाई चित्तेरी झील के प्रमुख पुनरुद्धार कार्य का हुआ उदघाटन

जिला कलेक्टर ने किया जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, तिरुनीरमलाई चिट्टेरी झील के जीर्णोद्धार कार्य का आधिकारिक रूप से शुरू किया गया। उद्घाटन का नेतृत्व चेंगलपट्टू के जिला कलेक्टर, आईएएस थिरु एस. अरुणराज और एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त, आईएएस थिरु एलेक्स पॉल मेनन ने किया। एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, तांबरम ने पर्यावरणविद फाउंडेशन ऑफ इंडिया (ईएफआई) के साथ मिलकर तिरुनीरमलाई चिट्टेरी झील को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इस महत्वपूर्ण बहाली परियोजना को शुरू किया है। इस बहाली का उद्देश्य चेन्नई बाईपास रोड के पश्चिमी परिधि पर स्थित झील की जल भंडारण क्षमता को बढ़ाना और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना है।

व्यापक पुनरुद्धार योजना में इपोमिया और प्रोसोपिस जूली वनस्पतियों जैसे आक्रामक वनस्पतियों को हटाना, बांध क्षेत्र से कचरे को साफ करना, गाद निकालने के प्रयासों के माध्यम से झील की भंडारण क्षमता को बढ़ाना, तटबंध को दोहरे बांध में बदलना, स्थानीय पक्षी जीवन को सहारा देने के लिए 5 घोंसले के द्वीपों की स्थापना करना, जलीय आवास की जटिलता को बढ़ाने के लिए 7 अवरोध बिंदुओं की स्थापना करना, जल पुनर्भरण में सुधार के लिए 3 पेंडुलम कुओं का निर्माण करना, भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए एक रिसाव खाई का निर्माण करना, सुरक्षा के लिए झील के चारों ओर बाड़ लगाना और जैव विविधता को सहारा देने के लिए देशी वनस्पतियों को लगाना शामिल है।

ईएफआई की ओर से ₹50 लाख के निवेश से जीर्णोद्धार कार्य 85 दिनों के भीतर पूरा होने का अनुमान है। इस सहयोगात्मक संरक्षण प्रयास का उद्देश्य झील को पुनर्जीवित करना, स्थानीय पारिस्थितिकी का समर्थन करना, आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ को रोकना और इस आवश्यक पड़ोस के जल निकाय की रक्षा करना है। चेंगलपट्टू के जिला कलेक्टर, एस. अरुणराज, ने कहा, तिरुनीरमलाई चिट्टेरी झील का जीर्णोद्धार एक महत्वपूर्ण पहल है जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह परियोजना न केवल झील की क्षमता को बढ़ाएगी बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुदाय का भी समर्थन करेगी।

एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त, थिरु एलेक्स पॉल मेनन, आईएएस ने कहा, पर्यावरणवादी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग करते हुए, हम इस महत्वपूर्ण जल निकाय को बहाल करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं। यह परियोजना दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने में समुदाय और सरकारी सहयोग की शक्ति का उदाहरण है। इस परियोजना का सफलतापूर्वक पूरा होना इस क्षेत्र में पर्यावरण बहाली के प्रयासों में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि तिरुनीरमलाई चित्तेरी झील लोगों और वन्यजीवों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करती रहेगी।

सिद्ध परमात्मा पर श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है : युवाचार्य महेंद्रऋषि

नार्थ टाऊन में धर्मसभा का आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। श्रमण संघीय युवाचार्य महेंद्र ऋषिजी महाराज आदि का बुधवार सुबह नार्थ टाऊन (बिन्नी मिल्स) के एएमकेएम भवन में आगमन हुआ। वहां प्रवचन में उन्होंने कहा कि उत्तराध्ययन के 36वें अध्ययन में भगवान महावीर ने कहा था कि तीन बातों सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के साथ किसी भी भव्य आत्मा की आयुष्य पूर्ण होती है तो वह जागृति को धर्म की शरण मिलेगी। जो व्यक्ति केवल इस जीवन को ही संपूर्ण मानता है, आगे पीछे की नहीं सोचता तो वह जानता है, यह जीवन का पड़ाव है, यह कब पूरा हो जाएगा, नहीं पता। जो यह जानता है, विश्वास रखता है, जो जागृत हैं, उसे पता है, प्रत्येक क्षण का कैसे उपयोग करना।

उन्होंने कहा जीवन के हर क्षण को सार्थक करना है तो ऐसी जागृत वाला सम्यक दर्शन से अनुराग रखने वाला हो। सम्यक दर्शन जैन धर्म, जैन दर्शन, मोक्ष मंजिल की नींव है। जब तक दर्शन नहीं, तब तक ज्ञान नहीं। जब तक ज्ञान नही, तब तक चारित्र नहीं। जब तक चारित्र नहीं, तब तक मोक्ष नहीं। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन का अर्थ, स्वरूप, आचरण को समझना जरूरी है। सम्यक यानी यथार्थ, जैसा है वैसा, सही। दर्शन यानी दृष्टि या आस्था। हमारी सही दृष्टि होनी जरूरी है। आज सब ओर अंध श्रद्धा का बोलबाला है। वहां सम्यक दर्शन की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन का मतलब है भीतर में रहे हुए सामर्थ्य को पाना। उसमें हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। वीतराग के दर्शन कर भौतिक सुख सुविधा मांगना अज्ञानता है। आप जिनके दर्शन कर रहे हो, उनके वास्तविक स्वरूप को समझो। अपने आत्म तत्व पर विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए। सिद्ध परमात्मा पर श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है।

मेरा जीवन, मेरी जीवात्मा सिद्ध जैसी निरंजन, निर्विकार, शुद्ध बने, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह अकेला होता है। वह दो पांव से चलता है, ज्ञानीजन कहते हैं विवाह कर दो के चार पांव हो जाते हैं और चार पांव वाले की हालत कैसी होती है, वह हम जानते हैं। बच्चा हो जाता है तो वह छः पांव वाला यानी भंवरा बन जाता है। फिर एक बच्चा हो गया तो आठ पांव का मकड़ी जैसा बन जाता है। इसी में उलझा हुआ जीवन होता है, जीवन इसी चक्कर में खत्म हो जाता है।

उन्होंने कहा, हमें परमात्मा के वचन में श्रद्धा होनी चाहिए। जिसकी दृष्टि सही है, उसमें श्रद्धा होती है। साधना, साधुत्व वही है। जिसकी नजर, नजरिया स्पष्ट है, वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन साधुत्व भावों में हैं, संयम के प्रति जागरूकता में है। साधुत्व पूर्णतः मन वचन और काया से भावों की निर्मलता पर निर्भर करता है। आठ प्रवचन माता से साधुत्व का पालन पोषण होता है, तभी संयम सुरक्षित रहता है। मैं आत्मा हूं, इसमें श्रद्धा है तो धर्म की शरण मिलती है। सम्यक दर्शन वही, जो खुद के लिए हो। आत्मा का सुख ही तीनों लोक में श्रेष्ठ है। जिससे अंतःकरण में प्रसन्नता हो, आनंद की भावना से जो धर्म करते हैं, वह सम्यक दर्शन है। हम सब अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ें। इस दौरान महिला मंडल ने भाव भरा स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर नार्थ टाऊन स्थानकवासी जैन संघ के अध्यक्ष अशोक एम. कोठारी, मंत्री ललित बेताला, प्रमोद ललवानी समेत कई गणमान्य उपस्थित थे। युवाचार्यश्री की अगले दो दिन नार्थ टाऊन में स्थिरता रहेगी, जहां सुबह 9 से प्रवचन होगा।

मंदिरों की संस्कृति ने ही बचाया है भारत राष्ट्र को : आचार्यश्री विमलसागरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु। शहर के नजरबाद स्थित शिक्षक भवन में आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत मंदिरों की संस्कृति का देश है। मंदिर मानव-सभ्यता के बहुत पुराने आविष्कार है। आराध्य के प्रति श्रद्धाभावना, आध्यात्मिक साधना और धर्म की रक्षा के लिए मंदिरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आतितायियों के परतंत्र काल में धर्मांतरण को रोकने और समाज को धर्म के प्रति निष्ठावान रखने का उल्लेखनीय कार्य मंदिरों की संस्कृति ने किया है। आज भी मंदिर धर्म के रक्षक हैं, मनुष्य के आत्मबल के आधार हैं, संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं और धर्मश्रद्धा के अनन्य केंद्र हैं। बुधवार को जैनाचार्य अपने शिष्य-प्रशिष्यों के साथ अनेक जिनमंदिरों की दर्शन परिक्रमा के लिये निकले। पुराने शहर के सुमतिनाथ जिनालय में संगमरमर की करीब 550 वर्ष पुरानी तीर्थंकरों की ऐतिहासिक प्रतिमाओं के समक्ष उन्होंने चैत्यवंदना की। मैसूर के जैन समाज की यह ऐतिहासिक धरोहर है। शहर में नये-पुराने आठ जिनमंदिर हैं। इस अवसर पर आचार्य विमलसागरसूरीश्वर ने बताया कि कभी कर्नाटक में हजारों की संख्या में प्राचीन जैन मंदिर अवस्थित थे। आज भारत भर में 75 हजार से अधिक जैन मंदिर मौजूद हैं। विदेशों में भी 200 से अधिक जिनमंदिरों का भव्य निर्माण हो चुका है। तीर्थंकरों के मंदिरों के निर्माण के लिये अपनी आमदनी का आधा से अधिक हिस्सा दान में दे देना जैन संस्कृति का विरल इतिहास है। जैन मंदिरों की पूजा-पद्धत्ति भी अनूठी और तार्किक है। यहां हर प्रक्रिया का रहस्यात्मक विवेचन हैं। जैन मंदिरों में प्रसाद के तौर पर भी कुछ न लेना, न खाना तथा मंदिर की किसी वस्तु या सुविधा का उपभोग न करना अत्यंत आवश्यक होता है। यहां परंपरा से जिनमंदिरों और जिनमूर्तियों की महत्ता, पूजाविधि और सारसंभाल के लिये हजारों ग्रंथों की रचना हुई हैं। जैन भक्तियोग का यह गौरवशाली अमूल्य साहित्य है।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Aditya at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.